

[Shri T. N. Singh.]

• mation about the person or persons who are involved in this. If the Government will care to go into this question I would welcome it. In any case I shall be obliged if within a short period the Government come out with some information that they are taking action in this and will set up an enquiry into this matter at an early date.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House Is adjourned till 2-15 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty-eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at quarter past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair. \*

#### DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF EDUCATION, SO- CIAL WELFARE AND CULTURE.

**श्री ओउम्प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश):**  
माननीय उपसभापति जी, आज मुझे ऐसे विषय पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो उसकी समस्त प्रगतियों का आधार होता है। भारतवर्ष को आज 25 वर्ष स्वतंत्र हुये हो गये, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा का जहाँ तक सम्बन्ध है, मैं उसके लिए शिक्षा मंत्रालय को और शिक्षा मंत्री को दोष नहीं देता, बल्कि मैं पूरी सरकार को दोष देना चाहता हूँ। उनकी योजना बनाने वालों को दोष देना चाहता हूँ, जिन्होंने और मंत्रालयों को तो महत्व दिया है, परन्तु शिक्षा मंत्रालय को अधिक महत्व नहीं दिया। जब बजट बनता है तो शिक्षा मंत्रालय एक कोने में धड़ा रह जाता है बेकार

लोगों की तरह और ऐसा लगता है कि मानो शिक्षा मंत्रालय ऐसा ही है कि उसमें कुछ काम स्वयं ही हो जायगा। शिक्षा को बजट में कोई महत्व नहीं दिया गया जबकि शिक्षा ही मूल आधार थी, इन तमाम योजनाओं की ओर यही कारण है कि आज सरकार के सामने सर्वत्र असफलताएँ नजर आ रही हैं। इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा की। आशा है कि अब सरकार इस पर ध्यान देगी। इसमें टूटा-टुटा जो भी कार्य हुआ है, उसके आंकड़े मैंने देखे। उनके देखने से ऐसा पता लगता है कि बहुत अधिक प्रगति हुई है। जहाँ 1961 में 49 विश्वविद्यालय थे, वहाँ अब 1971 में 93 हो गये हैं। जहाँ 1961 में कालेजों की संख्या 1,783 थी, अब वह बढ़ कर 3,604 हो गयी है। इसी प्रकार अध्यापकों की संख्या भी बढ़ी है। जो पहले प्रोफेसर्स 63,053 थे, अब '71 में 1,28,876 हो गये हैं, परन्तु जब यह देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ तो आश्चर्य हुआ और आज ही जो एक प्रश्न का उत्तर आया शिक्षा मंत्रालय की ओर से उसे देख कर मैं तो आश्चर्य में रह गया कि 1961 में जहाँ निरक्षरों की संख्या 33 करोड़ 30 लाख थी, वहाँ अब 1971 में सेंसस रिपोर्ट के अनुसार उनकी संख्या 38 करोड़ 60 लाख हो गयी है, यानी शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है और निरक्षरों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह एक आश्चर्य और खेद की बात है। फिर आंकड़ों में यह भी है कि जहाँ प्रगति हुई है उस के आंकड़े भी हैं। निरक्षरता दूर करने की दिशा में प्रगति हुई है। 1951

में निरीक्षकों का जो प्रतिशत था वह 16.67 था, 1961 में यह वह 24.02 रहा, अब 1971 में वह 29.34 रहा और इस दिशा में बढ़ोत्तरी हुई है, 5 परसेंट से 8 परसेंट, यानी 1951 से 1961 तक 8 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई और 1961 से 1971 में जहां पहले 24.02 परसेंट था अब वह 29.35 परसेंट हो गयी, वह भी प्रगति कर गये और निरीक्षरता की दिशा में केवल 5 परसेंट की प्रगति हुई। आजादी के समय 76 परसेंट के करीब निरीक्षरता थी, अब वह 71 परसेंट है, 5 परसेंट उसे आप दूर कर सके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा का मूल लक्ष्य एक बात को मानता हूं। बड़े-बड़े इंजीनियर्स, डाक्टरों, फिलासफर्स पैदा करना ही मैं शिक्षा का ध्येय नहीं मानता। शिक्षा का ध्येय मैं मानता हूं कि वह इंसान बनाये। अगर शिक्षा इंसान को इंसान नहीं बनाती और उसे केवल डाक्टर बना दे और उसमें इंसानियत न हो तो ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहां संस्कृत में आता है:

‘सक्षरा विपरीता: राक्षसा भवन्तु’। अर्थात् अगर पढ़ा लिखा आदमी गलत रास्ते पर चला जाय तो वह राक्षस बन कर खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि आज देश में साक्षरता की दृष्टि से पढ़े लिखों की संख्या तो बहुत बढ़ गयी है, परन्तु उन में जो इंसानियत की मात्रा थी वह घटी और इतनी घटी कि वह शून्य से भी ज्यादा नीचे गिर गई और उसका परिणाम यह हुआ कि

कोई भी आदमी, डाक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, चाहे मिनिस्टर हो, अपने पद पर रहते हुये काम नहीं करता, अपनी ड्युटी के लिये ईमानदार नहीं है और यही कारण है कि सर्वत्र भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। जिसका नाम राष्ट्रीय चरित्र है वह बिल्कुल गिर गया है। मैं आज की बात नहीं कहता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1966 ई० में इंग्लैंड से पानी के जहाज से आ रहा था, अलेक्जेंड्रिया पर जब जहाज आ कर रुका तो जहाज के कप्तान ने सब पैसेजर्स को बुला कर यह कहा कि अब यूरोप नहीं है, यूरोप खत्म हो गया है, यहां से मिडिल ईस्ट शुरू हो गया है, मिडिल ईस्ट से भारत तक अब आपको चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार मिलेगा और बेइमानी आदमी मिलेंगे, इसलिये आप बाजार में जाओ तो सावधानी से खरीदारी की बात कीजियेगा। इतनी ठेस लगी मुझको, जब भारत का भी नाम साथ में जुड़ा तो हमने कहा कि भारत के प्रति इस प्रकार का विचार है। तो राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान करने में आपने और शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया? यह मैं मानता हूं कि शिक्षा प्रान्तीय विषय है, किन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी हैं और यूनिवर्सिटी टैरिटरीज भी आपके पास हैं, आप आदर्श उपस्थित कर सकते थे परन्तु नहीं किया और आज सर्वत्र चरित्रहीनता का, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, झूठ और बेइमानी का बोलबाला है और इसका यह कारण है कि हमारी शिक्षा में चरित्र-निर्माण को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा, मेरा सुझाव है कि जब तक शिक्षा संस्थाओं में नैतिक

[श्री ओउम्प्रकाश त्यागी]

शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया जायगा, मारल टीचिंग को अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से नहीं लागू किया जायगा, चरित्र-निर्माण को भी शिक्षा का अंग नहीं बनाया जायगा, तब तक राष्ट्रीय केंरेक्टर बनेगा नहीं और जब राष्ट्रीय चरित्र नहीं बनेगा तो कोई भी योजना सरकार की सफल हो सकेगी, इसमें मुझे संदेह लगता है।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ और वह है प्राइमरी शिक्षा की बात। पहले भारतवर्ष में क्या रहा, कितनी संख्या पड़े लिखे लोगों की थी कितनी नहीं थी वह और बात है, लेकिन अगला भारत तो हम बना डाले, अगले भारत में तो पड़े लिखे लोग हो जायें, हम तो मौत के मुँह में खड़े हुये हैं, परन्तु जिन लोगों के हाथ में बागडोर देनी है वह तो पढ़ लिख कर खड़े हो जायें लेकिन इन 25 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार मैं यह देख रहा हूँ कि साक्षरता की दिशा में हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, जो आने वाली संतानें हैं, उनमें भी अपढ़ हैं। निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ी है, 8 करोड़ से अधिक की उनमें संख्या बढ़ी है। उसका मूल कारण क्या है कि पहले के निरक्षरों में नये निरक्षर बढ़े हैं। जो करोड़ों की संख्या संतानों में निरक्षरों की संख्या बढ़ी है उसका कारण क्या है। इसके दो मुख्य कारण हैं। यह देश शहरों का नहीं है, यहाँ पाँच हजार शहर होंगे तो बाकी 7 लाख से ज्यादा गांव होंगे, जहाँ कि सड़के नहीं हैं, कुछ नहीं है और वहाँ पर कहीं प्राइमरी स्कूल हैं आपके पास। एक-एक स्कूल बना दिया है दो-दो मील के फासले पर, तीन-तीन मील के

फासले पर। कहीं-कहीं स्कूल है और वह दो-दो या तीन-तीन मील के फासले पर है, तो पाँच या छः साल का बच्चा वहाँ कैसे पढ़ने के लिए जायगा। आपने यह जानबूझ कर किया है कि इस गांव के बच्चे पढ़ेंगे। इससे चुनाव में प्रभाव पड़ेगा और आपकी, कुर्सियाँ संकट में पड़ जायेंगी। आप जनता की निरक्षरता का लाभ उठा रहे हैं। जब तक हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं बन जाता, तब तक आप छः साल या पाँच साल के बच्चे को स्कूल में नहीं ले जा सकेंगे। परन्तु आज देश की यह स्थिति नहीं है। और उसके साथ-साथ एक चीज और है कि जो बच्चा स्कूल में आता भी है उनमें से भी 50 फीसदी बच्चे पाँचवीं या छठी तक नहीं रह पाते हैं, पहले दूसरे या तीसरे वर्ष में ही खिसक कर चले जाते हैं, वह नहीं पढ़ पाते। उसका मूल कारण है गरीबी। माता-पिता गरीब हैं, वे अपने काम धंधों में भी बच्चों की सहायता लेते हैं और उस सहायता लेने के लिए वे बच्चों को नहीं पढ़ाते।

दूसरी सामाजिक बीमारी भी है। आज ही जवाब दिया मंत्री महोदय ने और वह यह कि गरीबी के कारण भी बच्चे बहुत से स्कूल से हट जाते हैं। मैं मंत्री महोदय को सूचना देना चाहता हूँ, मैं गांव का आदमी हूँ और मैं जानता हूँ कि उसका कारण क्या है मास्टर्स में, अध्यापकों में अधिकांश सवर्ण लोग हैं जो कि, जो गरीब बच्चे हैं, हरिजनों के बच्चे हैं, उनको मारते हैं, तंग करते हैं, बेइज्जत करते हैं और ऐसा वातावरण स्कूल में बना देते हैं कि वे बेचारे तंग आकर स्कूल छोड़ देते हैं। आज अनुसूचित

जाति के लोगों में भी भावना है कि हमारे बच्चे बी० ए० पास हों, ग्रेजुएट हों, उनकी यह इच्छा नहीं कि उनके बच्चे उनके साथ काम करने जाएं। उनकी जो भी इच्छा हो, परन्तु स्कूलों में वह वातावरण मिल रहा है, जिसको छोड़ कर वे भागे जा रहे हैं। गरीबी भी एक कारण है, परन्तु यह भी इस प्रकार का एक कारण है जो मैंने बताया। यह मंत्री महोदय के हाथ की बात तो है नहीं, यह तो सरकार के हाथ की बात है और अगर सरकार को इस देश का कल्याण करना है तो प्राथमिक शिक्षा को केन्द्रीय विषय बना लेना चाहिए, तुरन्त यह भारत सरकार का केन्द्रीय विषय बन जाना चाहिए और युद्ध-स्तर पर, जिस प्रकार युद्ध की तैयारी के लिए हमारे मिनिस्टर भागे-भागे फिर रहे हैं कि ईरान हथियार पहुँच गए पाकिस्तान ने चाइना से आर्म्स ले लिए, यह ले लिया, वह ले लिया, तो जिस प्रकार हमारे डिफेन्स मिनिस्टर रशिया भागे-जा रहे हैं, तो उससे भी तीव्र गति से हमारे शिक्षा मंत्री देश के कोने-कोने में भागते फिरें और देखें स्कूल कहां बने हैं, कहां नहीं बने हैं। मैं यह मानता हूँ कि अगर एक बार हम शिक्षा के दृष्टिकोण से उठे, तैयार हो गए, तो संसार में हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा, हम तैयार हो जाएंगे। परन्तु शिक्षा को युद्ध-स्तर पर लेना होगा। और 6 से 11 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। जो माता-पिता न दे सके, उनको इसके लिए आर्थिक सहायता देनी पड़ी, तो वह भी दी जाए। उनके बच्चों को अगर दोपहर को भोजन नहीं मिलता है तो गवर्नमेन्ट की ओर से देना चाहिए। परन्तु आने वाली संतान को यह

13—13 RSS/ND/73

गवर्नमेन्ट कह सके कि अब देश में कोई बे-पड़ा-लिखा नहीं रहेगा। इस देश में पहले जो बे-पड़ा रहा सो रहा, लेकिन आगे इस प्रकार की स्थिति नहीं रहने दी जाएगी।

दूसरी समस्या है प्रौढ़ शिक्षा की। यह समस्या तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेन्ट ने जानबूझ कर हल नहीं की। शिक्षा डेमोक्रेसी का मूलाधार होती है। अगर वह सरकार प्रजातंत्र को स्वीकार न करती एक लोकतंत्र के स्थान पर राज-तंत्र स्थापित करती, फासिज्म और नाज़िज्म लेकर चलती तो मैं कहता कोई चिंता की बात नहीं है; क्योंकि उसमें तो पढ़े और बे-पढ़े सब एक डंडे से हाँके जाते हैं। परन्तु प्रजातंत्र को स्वीकार करने के पश्चात फिर देश में बे-पढ़े रहें और बे-पढ़े आदमी यह न जाने वोटिंग के मानी क्या है, वोट की क्रिमत क्या है, वह जाने नहीं प्रजातंत्र क्या है, तो फिर इस देश में डिमोक्रेसी एक ढोंग है। आज यही हो रहा है, एक ड्रामा बनाया हुआ है, जनरल इलेक्शन्स आते हैं, वोटिंग होती है और उपसभापति महोदय, मैं जानता हूँ, जाति के नाम पर, बिरादरी के आधार पर, ऊँच-नीच के नाम पर, वोटिंग होती है, बे-पढ़े आदमी आँख बंद करके वोट डाल देता है। पूछिए उनसे: भाई, कहां जा रहे हो? तो जवाब देगा: गऊ माता को वोट देने जा रहा हूँ। वोट गऊ माता को दे रहे हो या पार्टी को यह भी उसको पता नहीं। उनके दिमाग में यह है कि गऊ माता को वोट नहीं देंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा और इसी अनदता और निरक्षरता के ख्याल से ही माननीय बहिन प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने, गौ-रक्षा विरोधी होते हुए भी गऊ का चुनाव चिह्न लिया, यह निरक्षरता के पक्ष में इसीलिए, क्योंकि जब 1961 में 33 मिन लिय लोग बे-

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

पढ़ें, अब 386 मिलियन क्यों हो गए? बढ़ क्यों गई संख्या?

उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय के ऊपर मेरा विश्वास है, बहुत लायक आदमी हैं और मैं समझता हूँ वे जवाब देंगे तो योग्यता से जवाब देंगे, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब देश यह निश्चय कर लेता है कि देश में निरक्षर आदमी कोई नहीं रहेगा, तो फिर क्यों आज ऐसी स्थिति है? निरक्षरता 3 महीने में दूर हो सकती है, चौथा महीना लगने की जरूरत नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ चाइना का। चाइना ने अपने यहाँ सोच लिया था कि हमारे यहाँ निरक्षरता सरलता से तो दूर होनी नहीं। उन्होंने स्कूल और कालेजों को बंद कर दिया। विद्यार्थियों और अध्यापकों को आदेश दिया कि जितनी तुम्हारी डिग्रियाँ हो गई वह हो गई अब तुम जाओ देहात में। एक-एक गांव और चप्पा-चप्पा में चले जाइये और सब को साक्षर बना कर आइये। जब तक इस तरह की बात नहीं की जायेगी, तब तक हमारे देश में साक्षरता फैलने वाली नहीं है। हमारे यहाँ इतने कालेज हैं, इतनी यूनीवर्सिटियाँ हैं और इनमें से हजारों विद्यार्थी साक्षर हो कर निकलते हैं। इन लोगों का ग्रीष्म अवकाश होता है तो फिर इन लोगों का उपयोग चीन की भाँति साक्षरता फैलाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय हर साल रिपोर्ट निकालता है, आंकड़े देता है कि इस साल इतने स्कूल खोल दिये गये हैं और इतने बेकारों को नौकरी दे दी गई है। तो मेरा निवेदन यह है कि

गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, दो महीने की छुट्टी होती है, तो उसमें तमाम विद्यार्थियों को, प्रोफेसरों को और मास्टर्स को साक्षरता फैलाने के काम पर लगाइये और उनकी मदद लीजिये। अगर आप एक दो अवकाशों में इस तरह का प्रयोग करेंगे, तो सारे देश में बहुत काफी साक्षरता आ जायेगी, जिसके कारण काफी संख्या में लोग पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे और समाचारपत्र उनकी समझ में आने लगेंगे। लेकिन आजकल तो चुनाव की बीमारी है और यह एक ऐसी बीमारी है कि उस बीमारी में कोई भी आदमी जो उसमें प्रलोभन होता है, कुर्सी का प्रलोभन, वह उसको नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जो प्रौढ़ अशिक्षित है, वे साक्षर हो सकेंगे, इसमें मुझे सन्देह है।

मेरा सुझाव यह है कि आप ग्रीष्म अवकाश में मास्टर्स का उपयोग करें और साथ में जो रिटायर्ड आदमी हैं उनकी सेवाओं को इस काम में लिया जाय। इस समय देश में जितनी भी शिक्षा संस्थाएँ हैं, उनकी सेवा भी इस कार्य के लिए ली जाय।

दूसरी बात में ऊँची शिक्षा और कालेजों के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे यू०जी०सी० की ओर से इस तरह की संस्थाओं को सहायता दी जाती है। हमारी गवर्नमेंट धर्म निरपेक्षता में विश्वास करती है और वह जाति धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष की भावना से दूर है, परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई, जब मैंने कालेजों की वह लिस्ट देखी, जिनको सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। आज हमारे प्रान्तों में इस तरह की संस्थाएँ हैं, जो जाति के नाम पर स्थापित हैं, जो धर्म के नाम पर स्थापित हैं और इस तरह की संस्थाओं

को सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि कम से कम इस तरह की संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस तरह की सहायता केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जाती है और मंत्री जी यहां पर बतलायें कि यह सहायता किन किन संस्थाओं को कितनी कितनी दी जाती है क्योंकि मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े देखकर आया हूं। आपने काशी विद्यापीठ बनारस को, उसके अपने प्लान के लिए 3 लाख रुपया दिया है और नान-प्लान्ड के लिए 8 लाख रुपया दिया है। गुजरात विद्यापीठ को आपने दो लाख रुपया दिया है और नान-प्लान्ड के लिए 6.9 लाख रुपया दिया है। गुरुकुल कांगड़ी को उसके प्लान के लिए आपने 1 लाख रुपया दिया है और नान-प्लान्ड के लिए 6.30 लाख रुपया दिया है। जामिया मिलिया को आपने 3 लाख रुपया दिया है और नान-प्लान्ड के लिए 28 लाख रुपया दिया है। किसी को आपने एक लाख रुपया दिया है तो किसी को 28 लाख रुपया दिया है। तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि आप जो कालेजों को सहायता देते हैं उसका माप-दंड क्या है और किस आधार पर आप यह सहायता देते हैं? अगर आप पिछले आंकड़ों को देखेंगे तो आप को इस तरह की भिन्नता और भेदभाव दिखलाई देगा। मेरा कहना यह है कि आप सभी कालेजों तथा इस तरह की संस्थाओं को समान रूप से सहायता दें ताकि वे सब ऊंचा उठने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह की नीति पर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

उपसभापति जी, मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विशेष

रूप से कहना है। केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है और जो भी शिक्षा मंत्री साहसवाला, देशभक्त या ईमानदार आ जाता है, तो वह अधिक दिनों तक यहां पर नहीं रहता है और उसको यहां से छोड़कर जाना पड़ता है। मुझे भय लग रहा है शायद वर्तमान मंत्री श्री नूरुल हसन साहब—मेरी दृष्टि में वे ईमानदार हैं और अच्छे आदमी हैं—भी रह सकेंगे या नहीं क्योंकि विश्व-विद्यालयों की समस्या सामने आई है। चाहिए तो यह था कि जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उन सब पर एक ही नियमावली लागू होनी चाहिए थी, इस नियमावली के नीचे जो विश्वविद्यालय चलना चाहते हैं वे चलें। साफ कहना चाहिए था कि हमारा देश सेक्युलर है, हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, किसी भी ऐसे केन्द्रीय विश्व-विद्यालय को सहायता नहीं दी जायगी जिसका सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे वह हिन्दू विश्वविद्यालय हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी हो। ऐसा नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि अब अलीगढ़ यूनीवर्सिटी का बिल पास हुआ, उस पर प्रदर्शन हुए। इतना ही नहीं चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं इसलिए केवल रूलिंग पार्टी ही नहीं विरोधी पार्टियां भी बेचैन हो रही हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, कहती है कि तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, एजीटेशन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विरोधी पार्टियों की भी मीटिंग हो रही है, उकसाया जा रहा है, सेक्युलर नीति के विपरीत भाषण और प्रचार चल रहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी के घर पर भी धरना दिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि इस प्रकार के आन्दोलन और प्रचार से आप लड़खड़ा तो नहीं

[श्री ओउम्प्रकाश त्यागी]

रहे, कहीं उसमें, अलीगढ़ यूनीवर्सिटी एक्ट में परिवर्तन करने तो नहीं जा रहे, जैसी कि मांग आ रही है और जो सेक्युलरिज्म के ढांचे में फिट नहीं बैठती।

संस्कृति के बारे में शिक्षा मंत्रालय का एक काम सांस्कृतिक प्रचार भी है। मैं पहले लोकसभा में रहा और अब यहां भी हूं, जितने मंत्री आए उनसे मैंने बारबार जानने की चेष्टा की है, पूछा है कि भारतीय संस्कृति की परिभाषा क्या है? भारतीय संस्कृति क्या है, उसके सिद्धान्त क्या है कोई नहीं बताता। तमाम संसार में एक देश भारत ही ऐसा है जिसकी संस्कृति नाम में है पर उसकी संस्कृति क्या है यह कोई नहीं बताता। विद्वानों की दृष्टि से किसी भी देश की आत्मा उसकी संस्कृति होती है, संस्कृति के बिना राष्ट्र मर जाता है। भारत की संस्कृति क्या है—नाच और गाना। ये ललित कला को संस्कृति मान बैठे हैं और उसी के जगह जगह केन्द्र बन रहे हैं, नाच का केन्द्र बन जाता है, गाने का केन्द्र बन जाता है और जब बाहर संस्कृति के प्रचार के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजना होता है तो नाचने-गाने वालों का दल भेज दिया जाता है, वह चला जाता है और उसका प्रचार हो जाता है कि हमारे इतने संस्कृति प्रतिनिधि मंडल चले गए और उन्होंने उसका प्रचार किया, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया—इतने विद्वान यहां से गए, अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए—कि इन फंडामेंटल्स का प्रचार हमने किया। महात्मा गांधी अन्त तक हमारी संस्कृति का प्रचार करते करते मर गए। विदेशी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति पर ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारी संस्कृति

क्या है। आज मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे बताएं कि भारतीय संस्कृति के फंडामेंटल्स क्या है।

श्री बी० टी० केम्पराज : आप हो बता दीजिए।

श्री ओउम्प्रकाश त्यागी : मैं बताता हूं।

एक माननीय सदस्य : किसको बता रहे हो।

श्री ओउम्प्रकाश त्यागी : ऐसे आदमियों को बता रहा हूं जो समझ नहीं रहे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने सांस्कृतिक प्रचार के लिए क्या किया? आपकी रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें एक साहित्य अकादमी है। मैंने सोचा कि इसने कुछ किताबें लिखी होंगी। उसमें नावल और ड्रामा भरे पड़े हैं। तो सांस्कृतिक प्रचार नावल और ड्रामा भी हो सकता है, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि पहले तो आप यह बतायें कि हमारी संस्कृति क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। इसके प्रचार के लिए आपने क्या किया है। मैं स्कूल में बच्चों को देखकर आपसे पूछता हूं कि वह बच्चे जानना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। आपने इसके लिए क्या साहित्य तैयार किया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि किसी देश का अभिमान और गौरव उसकी प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर होता है। क्या भारतवर्ष का प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास नहीं है? भारतीय संस्कृति



का इतिहास नहीं है जिसके चिन्ह आज बेबीलोनिया, मंगोलिया, इंडोनेशिया में मिलते हैं? तमाम दुनिया के विद्वानों ने भारतीय संस्कृति पर ग्रन्थ लिखे हैं। लेकिन हमारे यहां कोई भी ग्रंथ तैयार नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि क्या आपने इस प्रकार का साहित्य तैयार कराया?

इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से अपने संबंध अन्य देशों से स्थापित करे। ठीक है, यह देश गरीब है, आर्थिक दृष्टिकोण से हम दूसरों की ज्यादा सहायता नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्राचीन काल से मध्य एशिया और अरब के देशों के और दक्षिण एशिया के देशों के लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमारा देश केन्द्र रहा। बगदाद जो आज हमारा विरोधी होकर खड़ा हो गया है, जब भारतीय संस्कृति का मिडिल ईस्ट सांस्कृतिक केन्द्र होता था वहां ग्रन्थों के ट्रांसलेशन होते थे और वहां से भारतीय संस्कृति ग्रीस होती हुई यूरोप में जाती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके डिपार्टमेंट में एक विभाग है इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च। नाम बहुत सुन्दर है। इतना सुन्दर नाम है कि मैंने सोचा शायद कोई सोशल साइंस पर रिसर्च की होगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च विभाग की ओर से कितने ग्रन्थ लिखे गये हैं, कितने ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और किन किन विषयों पर रिसर्च हो रही है। विशेष रूप से मैं यह जानना चाहूंगा कि वह कौन सा सामाजिक विषय है जिस पर इस इंस्टीट्यूशन में रिसर्च की गई है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में हमारे सामाजिक ढांचे पर

क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे सामाजिक नियम और साधनों पर वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति का असर और प्रभाव पड़ रहा है, इसके सम्बन्ध में कोई ग्रन्थ आपके यहां से लिखा गया हो तो आप उस सम्बन्ध में संकेत करें।

अन्त में, चूंकि घंटी बज चुकी है, एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय को 7 करोड़ का धन दिया है, यू० जी० सी० को आपने 31 करोड़ का धन दिया। दिल्ली की आबादी 40 लाख है, तमाम 55-56 करोड़ देश के लोग हैं, आपने उन के लिए केवल 24 करोड़ रखा और दिल्ली को 7 करोड़ रुपया दिया। यह दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ आपने अन्याय किया। यानी आधी परसेंट जनता को 7 करोड़ दिया है तो यह किस आधार पर दिया है?

एक और बात मैं जानना चाहूंगा। दिल्ली में प्राइवेट कालेज चल रहे हैं। उन्होंने खून पसीना एक करके घर-घर जाकर चंदा मांगकर वे प्राइवेट कालेज खोले हैं।

आर्य समाज की ओर से मैं कहता हूं कि हमने न मालूम कितने इंस्टीट्यूशंस खोले और उन के लिए मालूम नहीं किस तरह से चंदा मांगा। अब जब नियंत्रण का प्रश्न सामने आया पहले आपने प्रबंध समिति में ट्रस्ट के 10 रखे थे, विश्वविद्यालय के 2 रखे थे और अध्यापकों के 3 प्रतिनिधि रखे थे और अब आपने ट्रस्ट के 3 आदमी कर दिये, 2 विश्वविद्यालयों के कर दिया और 5 अध्यापकों के कर दिये। जिन आदमियों ने उन कालेजों को बनाया है और जो लोग चंदा घर-घर मांग कर के उनको चला रहे हैं उनको अब आपने अलग फेंक दिया है। जब उनका इंस्ट्रुट ही नहीं रहेगा तो इसके माने यह है कि



[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत]

इन इंस्टिट्यूट्स को आप को स्वयं संभालना पड़ेगा, अन्यथा आप उनको प्रोत्साहन दीजिए और उनको अनुत्साहित मत कीजिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सहायता पहुंचा रहे हैं उनको आप उत्साहित कीजिए। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, इसमें दो रायें नहीं हैं कि पिछले 25 वर्षों में हमारे देश में साक्षरता का प्रचार हुआ है। इस में भी दो रायें नहीं हैं कि पहले के मुकाबिले में बहुत बड़ी धन राशि शिक्षा के ऊपर व्यय की जा रही है। इसमें भी किसी के दो मत नहीं हो सकते कि शिक्षा विभाग में एक से एक शिक्षाविद् आये जिनके हाथ इसका कार्यभार सौंपा गया। मैं यह भी मानती हूं कि शिक्षा को किस प्रकार ओरियंटलाइज किया जाय, किस पद्धति पर डाला जाय, किस प्रणाली पर चलाया जाय इसके बारे में शिक्षाविदों की एक नहीं अनेक मीटिंगें हुई और उन्होंने उसके ऊपर विचार विमर्श किया और न जाने कितने प्लान बने, लेकिन इन सब के होते हुए भी जब हम आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से अपने मुल्क पर नजर डालते हैं तो हमें कई खामियां नजर आती हैं। खामियां तो हर एक काम में होती हैं और उनको सुधारा जाता है, लेकिन हमें यह नजर आता है कि बुनियादी तौर से जहां तक शिक्षा का सवाल है हम लोग जबरदस्त गलतियां करते चले जा रहे हैं। हमारे देश की जरूरतों को देखते हुए, हमारे यहां की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बदली जानी चाहिए थी, हम उसे बदलने में बिल्कुल कामियाब नहीं हो पाये। जो डांचा अंग्रेजों ने रखा था करीब करीब

उसी डांचे के ऊपर हम आज भी चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो डांचा अंग्रेजों ने हमारे यहां रखा था और वह केवल क्लर्क पैदा करने का रखा था और बदनसीबी से आज भी हम केवल क्लर्क पैदा करते चले जा रहे हैं, बल्कि मैं यह कहूंगी कि आज जो हमारा शिक्षा विभाग है वह बेकारों की गढ़ने की एक टकसाल है जहां लाखों बेकार नवयुवक गढ़े जा रहे हैं।

इसके अलावा जहां मुझे परेशानी होती है वह शिक्षा विभाग की एक नीति को देख कर होती है और वह यह है कि हम अपने मुल्क को जिस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, जिस तरह की हम अपने यहां की शासनप्रणाली चलाना चाहते हैं या जिस दिशा में हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा उसके विपरीत जा रही है। यदि हम मुल्क को ले जाना चाहते हैं पश्चिम की ओर तो शिक्षा ले जाती है पूर्व की ओर। देश में हम सोशलिज्म लाना चाहते हैं, देश को हम सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं और मुल्क को उस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली है कैपिटलिज्म पर आधारित। हमारी सरकार समाज में या राष्ट्र में जो सुधार करना चाहती है उसके संबंध में हमारी शिक्षा कोई सहयोग नहीं देती है। इसी का आज यह नतीजा है कि हम अच्छी से अच्छी नीतियां बनाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता और इसलिए नहीं हो पाता कि कालेजों से निकल करके जो ऐडमिनिस्ट्रेटर अपने पास आते हैं वे आज की बुनियादी नीतियों के बिल्कुल खिलाफ हैं क्योंकि उनको जो शिक्षा मिली है वह आज की बुनियादी नीतियों के खिलाफ है। इसलिए आप अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं पूर्व की ओर, लेकिन जो उसमें बैल जुड़े हुये हैं वे

उसे ले जाते हैं पश्चिम की ओर। सब से बड़ी मुश्किल यह है। आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं और आप अपने मुल्क को सेकुलर बना रहे हैं। उसके ऊपर आप को नाज है, लेकिन आप जो इतिहास पढ़ा रहे हैं उस में मुस्लिम पीरियड का इतिहास है और आप की शिक्षा उस के साथ मेल नहीं खाती। आप का मुल्क गरीब है। आप चाहते हैं कि यहां लेबर की डिमिन्टी हो, लोग लेबर की डिमिन्टी को समझ लें, लेकिन मंत्री महोदय आप जानते हैं कि हमारे कालेजों से या हाई स्कूलों से जो लड़के निकलते हैं वह लेबर के नाम से ही दूर भागते हैं। हम रात दिन देखते हैं कि हमारे गांवों के जो लड़के हैं उन के मां-बाप किसान होते हैं, वे अपने हाथों से ही अपना काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लड़का स्कूल में गया उस के बाद वह एक सेर वजन उठाने में भी अपनी तौहीन समझता है। लेबर की कोई डिमिन्टी उस के दिमाग में नहीं होती। इस लिए आप जिस तरफ मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं वह चल नहीं पा रहा है। आप जानते हैं कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार हो और गांव अपने आप में सेल्फ सफीशियेंट बनें, इंडिपेंडेंट बनें और गांव में रह कर ही लोग अपने गांवों की तरक्की करें, लेकिन बदनसीबी से जैसे ही गांव का लड़का शहर में आता है उस के बाद वह गांव में वापस जाना पसंद नहीं करता। अगर वह जाता है तो एक नयी प्रणाली, हिप्पी प्रणाली ले कर वह गांव में जाता है जो उस गांव में उस को अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। तो शिक्षा मंत्री महोदय, जो हमारी सब से बड़ी खामी है वह यह है कि जिस तरफ हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस के लिए उस तरह की शिक्षा हम

नहीं दे रहे हैं। अगर मैं आप को इस के संबंध में उदाहरण दूं तो उस में समय लगेगा और मैं समझती हूं कि इस की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखते हैं तो पाते हैं कि उस मुल्क के कर्णधार उस मुल्क को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उसी तरह की शिक्षा भी देते हैं। वह उन की दिशा चाहे गलत हो या सही हो, यह मैं नहीं कहती और मैं उस में जाना भी नहीं चाहती, किन्तु हिटलर जब जर्मनी में आया तो वह अपने मुल्क को योरप में एक फौजी ताकत बनाना चाहता था और इस लिए उस ने शिक्षा के हर पहलू में फौजी की शिक्षा को रखा। मैं यह नहीं कहती कि वह सही था, लेकिन अरिथमेटिक में यदि कोई सवाल भी अगर वहां होते थे तो वह इस प्रकार के होते थे कि अगर एक बम वर्षक एक घंटे में इतने बम गिराता है तो चार घंटे में कितने बम गिरायेगा। यानी बचपन से ही बच्चों को जिस दिशा में ले जाना होता था उस दिशा में बढ़ाया जाता था। उस के पतन के पश्चात् जब जी० डी० आर० ने अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलने का विचार किया तो वहां की हुकुमत ने सब से पहला काम तो यह किया कि जो वहां के पुराने शिक्षक थे, जिन के दिमाग में नाजियों का कीड़ा घुसा हुआ था या उन की आइडियोलोजी जो उन के दिमाग में बैठी हुई थी, सब से पहले उन शिक्षकों को वहां से हटा दिया गया। और उन को पढ़ाने का काम किसी भी स्कूल में नहीं दिया गया और उन के स्थान पर उन्होंने अपनी आइडियोलोजी के शिक्षकों को रखा। यह भी एक बड़ी दिक्कत थी कि उन के पास अपनी आइडियोलोजी के ज्यादा शिक्षक नहीं थे, तो उन्होंने कुछ शिक्षकों की सहायता

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत]

से वे दूसरे शिक्षक तैयार किये और फिर उन शिक्षकों को स्कूलों में भेजा गया। लेकिन आप सोचिये कि आज आप के शिक्षक क्या करते हैं और आज यहां की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है। आज आप सेकुलरइजम का बार बार दावा करते हैं, लेकिन क्या आज आप के स्कूल सांप्रदायिक चीजों का अड़्डा बने हुए नहीं हैं? क्या आज वहां सांप्रदायिकता के बीज नहीं बोये जा रहे हैं? मैं कहती हूं कि आपके मिडिल स्कूलों से ले कर यूनिवर्सिटी तक आज सांप्रदायिकता के बीज ही नहीं बोये जा रहे हैं, बल्कि वहां शिक्षा के साथ साथ कम्यूनलिज्म की शिक्षा और दीक्षा दी जा रही है। इस बात को आप को स्वीकार करना होगा। यह पहले हाई स्कूल्स तक था, अब यह बढ़ कर कालेजों और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। केवल हिन्दू यूनिवर्सिटी में ही कितनी शाखायें चल रही हैं। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कांड हुआ, आप के ही प्रदेश में वह क्या था? कल हमारे माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि नालंदा के बाद अपने ढंग का यह दूसरा अग्निकांड था जिस में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जलाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया गया। यह हमारी आंखें खोलने के लिए कम नहीं है कि यूनिवर्सिटियों में और कालेजों में इस तरह का तबका पैदा हो रहा है, पनप रहा है और फल फूल रहा है और मजा यह है कि दूसरे राज्यों में जहां इस प्रकार की शाखायें चलती हैं वहां उन को सरकारी ऐड दी जा रही है। मैं राजस्थान की मिसाल देकर कह सकती हूं कि "विद्या निकेदन" नाम की संस्था की जगह जगह पर ब्रांचें खुली हुई हैं उनमें खुलेआम इस तरह का प्रचार किया जाता है, इस तरह की शिक्षा

दी जाती है, इस तरह की दीक्षा दी जाती है। राज्य सरकारें जानती हैं, नियम भी ऐसे हैं, कायदे भी ऐसे हैं लेकिन अफसोस है कि इन मामलों में आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कुछ कर सकते, यह हमारी बुनियादी कमजोरी है और कमजोर बुनियाद के ऊपर शिक्षा का महल नहीं बन सकता, चाहे साक्षर हो जायें लेकिन शिक्षा का जो सही मंशा है वह पूरा नहीं होगा और जो आदर्श और उद्देश्य ले कर आप देश को आगे ले जा रहे हैं वह सपने इस शिक्षा को बुनियाद के ऊपर पूरे नहीं हो सकेंगे।

मैं आपका ध्यान कुछ दूसरी बातों की तरफ भी दिलाना चाहूंगी। शिक्षा को ले कर के आपके यहां नेशनल बुक ट्रस्ट चलता है। मैं जानना चाहूंगी कि आज तक उसका क्या क्या कांट्रीब्यूशन है। इस तरह से कई जगह है, इस तरह के अनेक ट्रस्ट या इस तरह के अनेक प्लान बना कर के सफेद हाथी शिक्षा विभाग में बांध रखे हैं जिनका कांट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता और खर्चा करोड़ों रुपयों का जाता है। मैं सिर्फ इसी का ही नहीं कहती हूं, दूसरे काम हैं, ट्रांस्लेशन का काम दे रखा है, अनेकों काम हैं, उनको देखा जाय तो करोड़ों रुपया खर्च होता है और जो हमारा मकसद है, जो मंशा है, वह पूरी नहीं हो पा रही है। हम फिर से ठीक से देख कर के कि इस महान राशि को कहां ठीक ढंग से खर्च करें जिसका कि सदुपयोग हो सके, यह देखना है। तो इस नजर से इसको देखा जाय।

जब हम अपनी साक्षरता और लिटरेसी की ओर ध्यान देते हैं तो अफसोस होता है। हमारा मुल्क शायद 338 मिलियन निरक्षर लोगों से भरा हुआ है। हमारे ताजे आंकड़े बताते हैं कि निरक्षरता बढ़ी है, आबादी के साथ

निरक्षरता भी बढ़ी है। अभी उधर बोलने वालों ने कहा कि अगर वो तीन महीने ग्रीष्म अवकाश में चले जायें तो साक्षर कर सकते हैं। मैं इस बात में विश्वास नहीं करती। यह बहुत बड़ा काम है। करोड़ों लोगों को शिक्षित करना, गांवों में जा कर के करना बहुत बड़ा काम है, उनका जो सामाजिक बैकग्राउंड है, जो आर्थिक स्थिति है उसमें जा कर के साक्षर करना बड़ा मुश्किल है। यह केवल अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। यह तभी हो सकेगा जब कि इसमें पब्लिक को, ग्राम जनता को, पीपुल्स को, उसमें डालें, एक ऐसा डाइव हो कि जो इस निरक्षरता को हटाने में दृढ़ हो और तभी यह हो सकता है। केवल सरकार के बूने पर करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी वह चीज नहीं हो सकती और न तो उसके लिए हमारी आर्थिक क्षमता है। दूसरे मुल्कों में हमने देखा है कि वहां ऐसा डाइव किया गया निरक्षरता को हटाने का और ग्राम लोगों ने उसमें सहयोग दिया। अगर स्कूल की बिल्डिंग न भी बने तो औरतें जो घर पर खाली रहती हैं वह बगंडे में बच्चों को बिठा दें और उनको साक्षर करें, औरतों को बिठा दें और उनको साक्षर करें। पहले बिल्डिंग बने, स्कूल बने, टीचर्स हों और उसके बाद जा कर यह हो तो उसमें कितना वक्त लगेगा। मैं आपसे कहूंगी कि आप जनता का ध्यान इसमें डालें, जनता से कुछ काम लें, जो खाली बैठे हैं, एक नहीं लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भलाई का काम भी करना चाहते हैं तो उन लोगों को साक्षरता के काम में लगायें। निरक्षरता को हटाने के लिए ग्राम जनता का सहयोग होना चाहिए। (Time bell rings)

14-13 RSS/ND/73

काफी वक्त है और बोलने वाले भी बहुत ज्यादा नहीं हैं। आप मुझे इजाजत दें।

**श्री उपसभापति :** बोलने वाले बहुत हैं यही तो दिक्कत है।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी खंडावत :** तो क्षमा कीजिए, मैं जल्दी जल्दी दो तीन बातें रखना चाहती हूँ।

हमने घाटं प्रिजर्वेशन का पिछले समय कानून बनाया था लेकिन उस कानून के अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने। बन भी गये हों तो मुझे पता नहीं लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर हो चुका है तो आप बताइयेगा कि कितने लोगों की ऐसी जो कलाकृतियाँ हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इतना अधिक वक्त लगने की वजह से लोगों ने उनको अंडरग्राउंड कर दिया है, उनको उन्होंने बेचना मुरु कर दिया है। इतना लम्बा समय जो लगा है उसकी वजह से यह हो रहा है। मैं आपका हैदराबाद के निजाम की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी। उनके पास एक बहुत बड़ा घाटं ट्रेजरी है। वह खुद यूरोप में रहते हैं।

चोरी-छिपे उस घाटं ट्रेजरी की बहुत दुर्दशा हो रही है, लोग वहाँ की चीजें चुरा रहे हैं, बेच रहे हैं, इधर-उधर ले जा रहे हैं। मैं नेशनल म्यूजियम की ओर भी थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। आपने 3 नेशनल म्यूजियम किए, अच्छा किया, लेकिन म्यूजियम में यह होता है कि अपने यहाँ की जो चीजें हैं वह तो हैं, बाहर की चीजें भी रखी होती हैं। अगर हम इस नज़रिए से देखें तो हमारे नेशनल म्यूजियम में बाहर की कला-कृतियाँ नहीं हैं जिससे बाहर की चीजें भी हम यहाँ के लोगों को पूरी दिखा सकें।

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत]

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी वह यह कि दिल्ली में, जहाँ कैपिटल है, हमारा एक नेशनल म्यूजियम है, वहाँ पर दर्शक लोग इतनी कम संख्या में देखने के लिए क्यों आते हैं? क्या आपने इसको स्टडी किया? मैंने सालारजंग का म्यूजियम हाल में देखा। रोजाना हजारों आदमी वहाँ आते हैं। जयपुर के म्यूजियम में भी करीब हजार की आसत है देखने वालों की। लेकिन यहाँ पर कम क्यों है? क्या जिस तरह की चीजें साधारण लोगों के देखने की होती हैं उस तरह की चीजें नहीं हैं। इसके साथ मैं निवेदन करूंगी कि हमारे म्यूजियम में जो लोग ज्यादातर रखे जाते हैं, यह इतना बड़ा स्टाफ क्यूरेटर का लगा कर, उनको म्यूरोलोजी की जानकारी कम होती है, न्युमिस्मेटिक की जानकारी कम होती है। कम से कम राजस्थान में न्युमिस्मेटिक जानने वाला कोई नहीं। उनकी ट्रेनिंग का किया जाना बहुत जरूरी है। (Time bell rings)

बार बार घंटी बज रही है। मैं एक ही मिनट में खत्म कर दूंगी। अब मैं आपका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ दिलाना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स को लेकर ओलम्पिक्स खेलों में जो हमारी गति हुई है वह सबके दिल को तोड़ने वाली है। श्रीमन्, और मुल्कों ने क्या कुछ किया है स्पोर्ट्स के मामले में और क्या हमने किया है? मैंने सुना है, कोई आपके हाथ में ऐसा प्लान है कि जिससे अलग अलग टीमों को फार्म करने के लिए, उसके लिए सेलेक्शन करने के लिए कोई पद्धति रखी गई है। चाहे पांच-बार स्पोर्ट्स ही हम चुनें लेकिन अच्छे लोगों को सेलेक्ट करके उनको बराबर तालीम दी जाए, उनके लिए अलग से

इन्स्टीट्यूट ट्रेनिंग और कोचिंग का हो और इसके साथ ही उनको छात्रवृत्ति के आधार पर जो नक़द धन आप देते हैं वह न दें बल्कि उनको खाना और खुराक दी जाए, क्योंकि जो रुपया दिया जाता है वह दूसरे कामों में खर्च हो जाता है। उन खिलाड़ियों को किस प्रकार अच्छी खुराक दी जाए, इसका आप पूरा प्रबंध करें (Time bell rings)

बार बार आप घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहूंगी। आपने मुझे बोलने के लिए जो वक्त दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sinani Lal Gupta, Kindly adhere to 15 minutj strictly. Otherwise we will have to sit up in 0.00 P.M. to finish it.

SHRI SHYAMLAL GUPTA (Bihar): Well, il you extend ii >\ an hour what is n rong with ii'

Mr. Deputy Chairman, Sir, we are advo eating secularism. We ari our edu- cational system on secularism. The Educa linn Ministei will kindly bear me out. \\\ his instance, ihr V.C. of the Delhi Uni- versity got passed resolutions from Acade mlc Council and Executive Council, as 111x friend Mr. Tyagi lir-t referred, to make differentiation between minority institu- tions, majority institutions and govern mini institutions. The V.C. has done it at the instance of lthe Education Minister, Prof. Nurul Hasan. Those trusts who had, spent about Rs. 10 to 12 lakhs on each insti iminii. They are now being condemned for doing 111 i ^ Bervice to the country. Although this lias not yel been cleared by the Ministry in by the Presideni bul the mischief has st:11 ted.

Sh. the i hans in the Delhi I fniversity, as we all know, is at its height. The staff councils nav< opposed the opening of even ing colleges and the administration of the Delhi University has given mo much fhtage m ihfii opinion or to thdr de cision. Last time also I mentioned about ii'< surplus staff. \\\v are spending about Rs- 1000 on each member of the stall' i'''1 hundreds of teachers ate surplus in J« Delhi University colli 1, n

of other Universities. My *Mend*, Mr. *fyagi*, mentioned about the money we spend on it, Delhi University. Will, during the Winter Session the report of the U.G.C. was presented and I spoke on it. Seven per cent was spent on (the Delhi University and the Jawahar Lal University) out of a total of Rs. 11 crores, on a half per cent population of the whole country. Now, is it secularism? Is it not famishing oil in an area where it is costly? We are over-feeding a small pocket. I am not against it. We should pay them more, but it should be equitably distributed rather than give region and famish the other regions. In Bihar the universities are not able even to pay the salaries of their staff and library books are not purchased by them. Illustrations have been mentioned in the report and "Jin. Our hon. Minister is aware of all these things and let him take a share of them. Kerala comes next. The Muslim League which is a partner in the parties forming the Government look exception in some portions in a text-book and lie-, agreed to it. Now, he may say that it is a State subject. The ruling party is having Governments everywhere. They are responsible for it. They had to take out the passage at the instance of the Muslim League. Is it secularism?

I come to the Banaras Hindu University. I have all the nominated members so far. What about that? Is the Vice-Chancellor, Dr. Shrimati, functioning well in this? In the reports, he does not take any democratic set-up there. In regard to the Aligarh Muslim University as my hon. friend just mentioned we have to appease the minorities, a Bill may come later shortly just to appease the minorities and to remove certain sections in which minorities are opposed.

Now, I may mention some other thing. I in- National Council for Educational Research and Training—NCERT—which is a wing of the Ministry of Education is responsible for the preparation of text-books, manuscripts and the sale of books. Our students are without books for six months because the officers working there are most inefficient. They are not able to provide textbooks to our students. I can prove it by whatever evidence the Minister may want me to produce. During the winter session I had asked the Minister of Edu-

cation about the working of the Hindi Directorate. We must have spent about Rs. in crores on its working during the past twenty years. Now, what is the result? In the Hindi Directorate had very kindly agreed to go into the details, but as is the case with all the Ministers, these have never looked into. I had specifically mentioned about the money you had advanced to publishers for translations of books which have never seen the light of day and they will never see the light of day. All the money has been wasted! Within all these things, the Hindi administrators just throw away money into the gutters. We say that the money allocated is less than what we want. Well, if the money which we budget for is well spent, then it can bring in a better result, than asking us for more money grants. In the Hindi Directorate Minister may or may not agree with me. But I am of this opinion that we do not spend the money in a rightful manner so, that more and more education could be spread by the money which we get. We do not waste money. The Ministry of Education should work well, the administrative charges should be much less than what it is at the moment. Will, I will not take time about that.

During the winter session, in reply to my question the Minister had very kindly consented to go into the details of the publications of regional books, translation of books into the regional languages. Nothing has been done so far. I have sent two or three letters to the Education Minister and to the Chairman of the University Grants Commission. But no reply has so far been received because these are questions which are unpalatable and why should the Education Minister or the Ministry's officers take cognizance of it? Well, we have millions of rupees and we are wasting it. Let the money be spent and not wasted. This attitude is very much against the welfare of the State.

Most of the States have nationalised books. Books are the media for the spread of education. I would request the Education Minister, Prof. Nurul Hasan, to collect those books and see the quality, whether we are able to provide books of a high quality in the students of those States. They are far behind the schedule when the colleges and the schools open. If a private publisher is not able to publish a book in time, then the State should publish it.

[Shri Shyamlal Gupta] clause, but there is no such penalty clause for the others. They are superhuman, they are above all others, they are the pillars of the nation. Now, Sir, take the National Library, Calcutta. Everything is in the doldrums. There is the Rajah Ram Mohan Roy Trust, but a error has been earmarked and what is the outcome! I see National Book Trust's publications are being dumped into the library. And after the money has been spent, we shall have a report that so much money has been spent on Rajah Ram Mohan Roy Trust Library although not much will come out of it. The National Book Production Board was started about 10 years ago. What is the outcome? What work have they done? What has the Government done to improve the productivity of books and what have they helped about the indigenous production of books which are the media of the education of children? As mentioned in the sister here, what about the athletes, about students' welfare? You are responsible for youth welfare also. Is it their welfare that in all the campuses the students are going in; out of the hands of the teachers and even the Vice-Chancellor is not able to control them. It is not because of the policy, but in Delhi the staff of a college have 18 periods to teach out of which 8 to 10 are preceptorials. Nobody is interested; the students or the teachers, they do not rate. Why? Because the University condones absence from them. The idea was that the idea was in having small groups of students to give them teaching, to sort out their difficulties. But actually it is not being done. Why? Because no one wants to work. Will the Education Minister kindly try to explain to him personally. He is a busy man and will not have time. I addressed him two letters about it but no reply so far has come. I do not think even to mention any fruit. But I think it is not to mention whatever I feel about it.

Sir, the surplus staff of the school. I said last time also, it creates a mismanagement. On in Delhi colleges we spend Rs. 7 million what is being done with this money? The surplus staff is there but 100 boys 10 teach. What is the waste (wasting so much money) of the

institution if the staff does not work? I have been mentioning this for the last two years for the Vice-Chancellor and even to the Chairman of the U.G.C. and the Minister himself but nothing has been done because of the indifference of the Minister and the Government. I hope the Government will shake. If we have to administer, these things should not deter us from the right path.

Others have taken up so many other things. I will not repeat. But I will request the Education Minister who is an enlightened person and a teacher himself to take action with the Government. We have mentioned in the past if he thinks it he may take us into confidence and we will certainly help him in many ways.

**पंडित भवानो प्रसाद तिवारी (मध्य प्रदेश) :** उप-सभापति महोदय, मैं आपके विवाद में सबसे पहले जो शिक्षा मंत्रालय में मंत्री हैं उनके द्वारा जो एक विशेष कार्य हुआ है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तहाँ प्रदेशों में ग्रंथ अकादमियाँ बनी हैं और उन पर द्रव्य खर्च किया गया है इसलिए कि भारतीय भाषाओं में वे ग्रंथ उपलब्ध हो सकें जो विदेशी भाषाओं में हैं और हमारे यहाँ नहीं हैं, जो तकनीकी ग्रंथ हैं जिनकी बहुत आवश्यकता है, तो जो काम विभिन्न सूत्रों में हुआ है, जो प्रतिवेदन आपा हैं इन ग्रंथ अकादमियों का वह बड़ा संतोषजनक है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जो योजना यहाँ से प्रसारित की गई थी कि जो किशोर और तरुण विद्यार्थी हैं उनको काम में लगाया जाए, छुट्टियों के वक़्त उनसे काम लिया जाए, श्रम भी और पढ़ाने का भी, जिन्होंने भी इस बात को पकड़ा है और जहाँ जहाँ यह काम हुआ है वहाँ उल्लेखनीय प्रगति दिखाई पड़ी है और एक प्रकार से उपद्रवों से विद्यार्थी बचे रहे हैं। जो यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध में, माध्यमिक



शिक्षा के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में अच्छी से अच्छी योजनाएँ चलीं और पाँचवीं योजना में क्या उपस्थित किया जाए वह भी अच्छी से अच्छी चीजें सामने आईं। सहानुभूति से विचार करने का, सोचने की बात यह है कि केवल इस वक्त ही नहीं, इन 25 वर्षों में शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालय ने अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन किया, समस्याओं पर अच्छे से अच्छे प्रतिवेदन उपस्थित किये हैं और फिर भी जो परिणाम प्रस्तुत है देश के सामने वह करीब करीब शून्य है।

ये छोटी छोटी बातें जो अभी कहीं उनको छोड़ कर । जो मुख्य कठिनाई शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री की है वह मैं इस तरह से सोचता हूँ कि सब से बड़ी विषमता जो संविधान ने शिक्षा की स्थिति की कर के रखी है वह इसका मुख्य कारण है और इसी मुख्य कारण में से अनेक विषमताओं ने फैल कर के शिक्षा के क्षेत्र को जो नहीं बनना था वह भी बना दिया। उदाहरण के लिए अच्छी से अच्छी योजना यहां से जाय और कोई प्रदेश उसे न लागू करे तो यहां से क्या किया जा सकता है। इसी तरह से अच्छी से अच्छी योजना प्राथमिक शिक्षा की भेजी जाय और जिन के हाथ में प्राथमिक शिक्षा चलाने का अधिकार है, चाहे वह म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वह कारपोरेशन हो, वह उसे लागू न करे, उस दिशा में न जाकर और दिशाओं में जाय तो क्या किया जा सकता है। इसी तरह से युनिवर्सिटियों में, उच्च शिक्षा में भी यहां से कोई नियंत्रण नहीं है। यू० जी० सी० इतना पैसा देता है और जिन को पैसा देता है वे स्वायत्त संस्थाएं हैं और उन स्वायत्त संस्थाओं में जो विद्यार्थी हैं वे बड़ी उम्र के हो जाते हैं कालेजों में पहुंच कर के और वे उच्छृंखल हो

गये हैं ठीक मार्गदर्शन के अभाव में या यह समझिये कि इन विषमताओं के प्रभाव से।

एक और यह मुख्य विषमता है कि शिक्षा की प्राथमिक शालाएं भी अनेक प्रकार की हैं जिन में अनेक शासन उनके उत्तरदायी हैं। ठीक इसी प्रकार सरकारी माध्यमिक शालाएं हैं, पब्लिक स्कूल हैं और और तरह के स्कूल हैं। इसी तरह से उच्च शिक्षा में भी प्राइवेट कालेजेज हैं और गवर्न-मेंट कालेजेज हैं और युनिवर्सिटी की अपनी शिक्षा अलग चलती है। कहीं पर युनिवर्सिटी कालेजेज को अफिलिएट कर के चलती है और युनिवर्सिटी का अपना शासन कालेजेज पर नहीं चलता है।

जो शिक्षक और शिष्यों के सम्बन्ध पुराने जमाने में चले आये थे वे सब टूट-फूट गये हैं। सब जगह द्रव्य चलता है, पैसा चलता है, पैसे से सब चीजों को खरीदा जा सकता है। फर्स्ट क्लास भी इम्तहान में, परीक्षा में, खरीदा जा सकता है और ऐसा होता है। आतंककारी प्रवृत्तियाँ शिक्षा के जीवन को प्रभावित कर रही हैं जो सर्वत्र दिखाई देती हैं। अभी कल ही उदाहरण यहां पर आया और जो कानून और व्यवस्था का प्रश्न था उसमें भी विद्यार्थियों का उल्लेख हुआ। पुलिस से विद्यार्थियों की सांठगांठ का एक नक्शा उपस्थित हुआ जिसमें लखनऊ में अराजकता की स्थिति पैदा की ओर एक भयंकर अग्निकांड हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। इन विषमताओं की जड़ को खाद कर जब तक नहीं बहाया जायगा तब तक जो भी बचन हम देते हैं, जो भी उद्देश्य हम सामने रखते हैं सब इसी प्रकार से असफल होते चले जायेंगे। कौन ऐसा ईमानदार शिक्षाविद् नहीं है जिस ने ऐसा महसूस न किया हो, यह स्वीकार न किया हो कि

[पंडित भवानी प्रसाद तिवारी]

शिक्षा की पद्धति को आमूल बदलने की आवश्यकता है, मगर जैसा कि संकेत किया गया कि कहीं कोई आमूल परिवर्तन हो नहीं सका। अच्छे से अच्छा रिमच बर्क हमने जरूर इकट्ठा कर लिया, पर हम किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सके। जो अभी त्यागी जी ने कहा उनकी बात को मैं दूसरी तरह से कहता हूँ कि गांधी जी ने इस संबंध में यह कहा था कि यदि शिक्षा में चरित्र निर्माण का कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं उसको कोई महत्व नहीं देता।

आज तो यह दिखायी देता है कि शिक्षा के क्षेत्र में चरित्र निर्माण की कोई गतिविधि नहीं है, बल्कि लोग उल्टी ओर चल रहे हैं और इस वजह से यह आवश्यक हो गया है कि सोचा जाय कि क्या कोई एक शायन इस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यानी ममझ लीजिए कि केन्द्र का शासन होता है, वह ही सारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को अपने हाथ में ले कर चले और वह पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हो ताकि हम यहां सरकार से पूछ सकें कि क्या कारण है कि आप के प्रयत्न करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, अच्छी से अच्छी योजना के नतीजे भी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वह बता सकें कि इस का कारण यह है। इस समय तो हम केवल एक ही उत्तर सुनते हैं कि यह तो हमारे क्षेत्र में नहीं है, यह तो स्टेट का विषय है, उस के क्षेत्र में है तो उस में हम क्या करें। यही स्थिति हमेशा पैदा होती है। इस स्थिति को बिना मिटाये, जो यह सैद्धांतिक विषमता इस की जड़ में है इस को बिना तोड़ न तो आप पद्धति बदल सकते हैं और न आप जो आदर्श बनाते हैं, जो आदर्श

उपस्थित करना चाहते हैं वह कर सकते हैं और ऐसा रहने पर आप चाहे अच्छे से अच्छा मार्ग दर्शन भी क्यों न दें परिणाम हमेशा घटता हुआ ही मिलेगा, अन्य ही मिलेगा और यह दुर्भाग्य की बात है। आप ने देश में सब कुछ बनाया। आप ने उद्योगों का निर्माण किया, खेती के औजारों का निर्माण किया, जो नयी दुनिया में आप का सपना हुआ उस से तरह तरह के निर्माण आप ने इस देश में किये, परन्तु पीढ़ी निर्माण आप नहीं कर पाये और उस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल विषमता पैदा हुई है और जिस का बड़ा हुआ क्षेत्र है, जिस के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, इस स्थिति को बिना मिटाये आप कुछ नहीं कर सकते और ऐसा न होने पर यह भराजकता बढ़ती ही जायगी और इस की कहीं रोक नहीं होगी। आप देखिये न, पहले विद्यार्थियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती थी, अब पुलिस और विद्यार्थियों की युति को रोकने के लिए मिलिटरी की आवश्यकता पड़ती है। यह क्या शिक्षा का क्षेत्र है? यह हम क्या कर रहे हैं? आप इन विषमताओं पर प्रहार करिये। शिक्षक आज बिक रहा है और जब वह बिक रहा है तो यह विद्यार्थियों को क्या सिखायेगा, क्या उन का चरित्र निर्माण करेगा। तो श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि अपने आदर्श और अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए इस विषमता पर आघात करना आवश्यक है।

जहां तक संस्कृति के मूल का प्रश्न है, मैं त्यागी जी से इस मामले में सहमत नहीं होता। वह हमेशा ही किसी न किसी बात में नाच गाने की बात छेड़ देते हैं।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : यह भी अच्छी बात है।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : मुनिये, मैं ने आप को सुना है। मैं आप से कहता हूँ कि आप ने कहीं संस्कृति की बात। कहां संस्कृति की परिभाषा कीजिए। परिभाषा तो इतनी सहज है कि युगों युगों से जो आप के आचार, विचार, सभ्यता, साहित्य और कला चली आ रही है यह सब कुछ आप की संस्कृति है और उस की अभिव्यक्ति विभिन्न विधाओं में होती है और जो विभिन्न विधाओं में उस की अभिव्यक्ति होती है उस में एक विधा आप का साहित्य भी है जिस में तुलसीदास आते हैं, सूरदास आते हैं, कबीरदास आते हैं और रवीन्द्र आते हैं जिन्होंने संदेश दिया सारी दुनिया को। एक विधा उस की संगीत भी है जिस में अभी अभी आपने विष्णु पलुस्कर का नाम लिया, रविशंकर जो दुनिया भर में सितार लिये फिरते हैं वह क्या भारतीय संस्कृति का संदेश नहीं देते ? (व्यवधान) मैंने तो अकेडमी की बात नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ कि यह संस्कृति का संदेश ले कर जाते हैं। आप अगर बीच में बोलें तो आप को होशियारी से बोलना चाहिए। मैं यह कह रहा था कि ठीक इसी तरीके से जो आप के नृत्य करने वाले हैं, जो कर्नाटक नृत्य और दूसरी तरह के नृत्यों के विचारद हैं वह अपने पुंखरुओं की शंकर के चलते ही भारतीय संस्कृति का संदेश देते हैं।

श्री ओडम प्रकाश त्यागी : श्रीमन्, एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं जरा साफ कर दूँ। मैंने यह कभी नहीं कहा कि नाच गाना संस्कृति का अंग नहीं है। नाच गाना भी संस्कृति का अंग है लेकिन यह संस्कृति का अंग है मूल आधार नहीं है। यह ललित कला है।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : यह सब कहा है, अच्छा, सुधार कर कहा है। मूल आधार मैं कोई नहीं मानता। मैं तो तीन विधायें बता रहा हूँ ललित कला की और यह भी कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक स्थितियों पर लोग जागरूक हैं, देश में जो तीन अकादमियाँ हमारे यहां चलती हैं उनके काम के सम्बन्ध में, उनके सम्बन्ध में, शिकायतें भेजी हैं, उनके ऊपर मंत्रालय की तरफ से कमेटी बनी खोसला कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी, शिकायतें दूर करने के उममें जो कुछ नये नये विधान हैं उन पर विचार हो रहा है तो मैं जानना चाहूंगा कि यह बात कहां तक आई और अकेडमी जो इन पर विचार कर रही थी तो वह कौन कौन से सुधार हैं जो अकेडमी स्वीकार करेगी और उनसे क्या परिवर्तन इन अकेडमियों में आयेगा।

तो इस तरह से यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक संदेश यहां से जावे, हमेशा जावे क्योंकि इतनी पुरातन संस्कृति और है नहीं जितनी हमारी संस्कृति है और इसीलिये मैं इसी बात को दुहरा कर खत्म करता हूँ। आप इ को पकड़ कर के उसको हटाइये, विषमता को दूर कीजिए, इस मुख्य विषमता को दूर कीजिए और जो विभिन्न विषमता फैली है वह आप से आप इसी में दूर होगी और एक नियंत्रित वागन हो जो कि जवाबदार हो देश के प्रति। क्यों शिक्षा का अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन हमारे पास हो कर के भी हम परिणाम कुछ पैदा नहीं कर सकते और एक अराजकता फैली हुई है।

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, to when fissiparous tendencies are really invading the deeper channels of national life, action is the all-out need on all fronts,

[Shri i khar Samal.j  
pmii ulaih in education. But I am sorry  
in sa\ tin real absence of purposefulness  
is the keynote of the present educational  
prirfcies ni tin Got We are talk-  
ing, grit ulturists and  
the underdogs. Bui university education is denied to  
80 per cent of these people. Eighty >i'i mil ni the  
people get only tinkering grants Eor primary  
education and twenty per cent of the people gel the  
cream ni iiii Government revenue for college and  
university education. The result is that even talented  
boys among the peasantry, after passing the primary  
education, in the absence of any opportunities Eor  
higher education either through proper scholarship  
or stipends or otherwise, they go hark to the plough  
and ihev forget the little education that they got in  
the primary .\it(\ ii is only the uppej class peo-the  
'\_ii en i em of the people, who gel the advantage of  
higher education through colleges and universities,  
have all die State advantages, advantages of  
Governra&rrt service, advantages ol education and  
all that. All these advantages are made available  
only io this <lass of people and they are literally  
denied to the underdogs. This is mil only a polk v  
against modernism, but also the Congress, I hope,  
has noi forgotten Mahatma Gandhi yet . . .

SHRI M. RUTHNASWAMY: They had  
forgotten him long ago.

SHRI SASANKASEKHAR SAWAI : I  
am glad you have said it. Even if Mahatma  
Gandhi ts to be remembered now and then,  
once in a blur moon, his basis of the basic  
'din .iiioii si heme was that the peoph . the  
majority ol the people, should be given  
such education which will make them ap-  
propriateiy applicable and adaptable and  
available for the public purpose in ac-  
cordance with the respective talents of these  
people. May I ask my friend Prof. Hasan  
who is not "lik. an educationist, but has  
chosen education as a career, whether lu-  
lus forgotten ail ah..... (he underdog.

Regarding these Publii Schools, I will  
give you *one* exarupl. In Dehra Dun there  
' .lmLi School. There is a rat race  
among the big people to gel theu children  
... Each student has ,,, spend  
Rs 7,000 month. Who are the pa-  
ke that? No doubt

ihev are blai k-raa rs. Ami this edu-  
cation is taken as stepping stone for fur-  
ther education, abroad. And they come bark  
to the country and sil on our shoulders.  
I'll.i means, blacl rs rule the  
country^ I am sorry to say that many of  
Ministers, if not all, are also sending I heir  
children to such schools, They do not send their  
children to institutions and's where 85 or  
11(1 pel cent of the children lake education.  
But they send children to such schools  
which arc I tin-national and anti-national.

I will now give you a startling disclosure. Ihe  
liank Anthony School in New Delhi Publil Scl  
L. Do you know that Oxford I  
niversity has published a book called "Certified  
Regional Geography Monsoon Asia". This book is  
(aught in that .school. And this is only one link in  
the i bain of Frank Anthony Schools all over the  
country, Frank Antho tp is not a stranger to ns. If  
von walk across the Central Hall to the other side,  
you will tind him. Now I will read a portion  
from Ibis book:

"this Himalayan State of si!,nun tq miles uiih  
its strategii location, its beautiful scenery and  
the source<sup>1</sup> of the Indus is in a difficult position."

This is about Kashmir. Then it goes on to say:

"80 pet tent ol its 5 million inhabitants are  
Muslims and wish to join Pakistan."

Shall I lead ii again for Prof. Hasan?

"This Himalayan State of 82,000 square  
miles with its strategii location, its  
be tutiful ;i in 11 and the source of the Indus is in  
a difficult position. Its Maharaja is a Hindu and  
joined Kashmir to India, bin 80 pel cent of its 5  
million inhabitants are Muslims and wish io join  
an."

It further sins . . .

ill) MINISTER OF EDUCATION, SO CIAL  
IVELI \RF. AND CI I I IRK (PROF. s. NURUL  
HASAN): May I request the lion. Member to let me  
have the name of that book?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: This  
is a publication by Oxford Univer-  
sity < of the book is "Certi-

15—13 RSS/ND/73

I can give you another instance to show how anarchy prevails in education. Sir, a gentleman, by name Shri D. H. Sharma— forget the name—was the Principal of the Government Higher Secondary School in

[Shri Sasankasekhar Sanyal.]

Subri Mandi in 1971. He got a State award for being a teacher of outstanding qualities. This is only an illustration. Now, according to the Government conventions and rules, the recipients of such awards get a medal and automatically they get two years' extension. So, after the extension, he to have retired in 1974. But, Sir, he was suddenly terminated on 30-10-1972 without assigning any reason. I am telling you this to show that such things are happening. After all, is it the whim of somebody in the department who lose these things? Is there any invisible ghost what haunts the directorate and directs its policy?

Therefore, Sir, I submit and maintain that the class character of education is there very much. It was not only there before, but also it is increasing now and it is because our representatives, the Ministers, are constantly in the pockets of these classes, these monopolists and the bureaucrats. These people are no longer directing our bureaucrats, but the bureaucrats are directing both the Ministers and those in the educational field. We are in the same darkness. We asked: Let there be light. But there was no light. There was eternal darkness and there is eternal darkness and it continues to be eternal darkness only. Thank you.

[THE VICE-CHAIRMAN CSHRI V. B. RAJU) in the Chair]

SHRIMATI RATHNABAI SREENIVASA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, today the education system in our country presents a dismal picture. After 25 years of Independence we are still carrying on the burden of the system imposed on us by the Britishers. While the system needed a thorough overhauling to suit the needs of our country, we have tried to do sporadic patch work here and there by making some changes in the curriculum or syllabus on a number of years of schooling, etc., which have had only adverse effects. Our children have become victims of our half baked experiments. The whole system of education at all levels needs radical reforms.

The Government had given us an assurance that within ten years of the promulgation of the Constitution, education

will be made free and compulsory up to the age of 14 years. But today there are more than 386 million illiterates in our country as compared with 298 million in 1951. We have more than half of the world's illiterates. With the majority of the masses illiterate, we cannot make any headway towards progress. Subjects of Food and Education should receive top priority in our planning. But the Budget allotment under Education is very inadequate. In the Fourth Plan the allocation is only Rs. 824 crores which is 5.2% of the total outlay and in Fifth Plan, though it is Rs. 2200 crores, it is only 6.4% of the total outlay. In tackle the stupendous problem of illiteracy, at least 10% of the total outlay should have been allotted to Education. However, I am glad that in the Fifth Plan, primary education rightly gets a priority by getting Rs. 1,100 crores, i.e. 80% of the allocation on Education and a considerable outlay has been proposed on vocationalisation of studies at the High School level.

Sir, I know that a great deal of progress has been achieved in the provision of educational facilities and the bulk of the hitherto deprived of educational opportunities have had increased access to education. But this expansion has not kept pace with our needs of the time. The rapid expansion has created many new problems and has failed to achieve the benefits expected. The more outstanding of the problems are, one, a deplorable decline in the quality of education and, two, creation

of high expectation in the young, without providing them with the resources or opportunities to fulfil them. Young educated men and women are choosy about their jobs. Even the rural educated youth want jobs in cities only. This has created not only the problem of large-scale un-

employment among the educated, but it is also responsible to a great extent for the highly explosive situation prevailing now in the educational institutions. Indiscipline, communalism and politics have seeped into the field of education also. Copying in examinations—that too mass copying—has become a normal feature of the day and students feel it is their right and privilege to copy. Not a day passes when we do not hear of agitation, violence and anarchy in educational institutions somewhere in the country. This means that no importance is

attached to the content of education but only to the degree. Character building and a national outlook should be the main objective of education and our educational system, including the system of examination, needs radical reforms.

I admit that the Government is making efforts to raise the standards of education at all levels. The proposal to establish model community schools at the block levels and District level, intended to be pace setters, with modern curriculum and adequate hostel facilities, is welcome as an attempt to raise the standards of education. It is heartening to note that 25% of the seats will be reserved for children coming from the socially and economically backward groups and that they will be given full maintenance grants.

While the Central Schools, or Kendriya Vidyalayas, are maintaining a high standard of education, we should also be careful that we are not laying the foundation for another class conscious group in our society. These schools must be open to all children who possess merit and qualifications and some seats for deserving children of the poorer classes should be reserved and these should get full maintenance grants.

I welcome the educational technology project for providing integral instruction by making use of films, radio broadcasts and new educational techniques.

Just as the Government has established Central Schools in all parts of the country, Central Universities should also be established in all parts of the country to bring together the youth from all parts of the country and to enable them to live in harmony and friendliness, thereby promoting national integration. These Central Universities should be free from a communal character whether of a majority community or of a minority community. While on this subject, I would request the hon. Minister to consider the possibility of establishing a Central University in Andhra Pradesh.

While I do not hold that higher education should not be open to all, I feel that admission should be regulated and only those who have an aptitude for

higher studies should be admitted. We have to keep in mind the stupendous problem of unemployment and be aware of the fact that we cannot go on producing graduates, engineers or doctors, without giving into consideration the employment opportunities. High priority should be given for vocationalisation at the Higher Secondary stage so that many people will be in a position to go in for a vocation after finishing the Higher Secondary School. If such people wish to continue their studies, opportunities should be provided for them by opening evening classes in colleges wherever necessary.

One of our major problems is that of the out of school youth between the ages of 14 and 25 years. Both Government and voluntary welfare institutions should make all efforts to provide these young people opportunities for physical culture, recreation as well as continuing their studies if they so wish. Their cooperation should be sought in all our programmes of nation building so that they develop a modern outlook and a sense of identity with our national aspirations. I hope that the Yuvak Kendras proposed to be established in the Fifth Plan and the youth movement will go a long way to achieve this object and to bring the non-student and student youths together and help them understand each other and help each other.

I have a word to say about the status of teachers, especially at the elementary level. We are told that by the end of the Fourth Plan, an additional total number of 90,000 teachers are expected to be provided for as one of the measures to tackle the problem of educated unemployment. But we should take care that we draw only the best talents to this most important profession. Only those who have passed meritoriously in their qualifying examination and only those who have an aptitude for teaching should be selected as teachers and their remuneration should be adequate to attract really good teachers.

Finally, I think that education should be a concurrent subject. The States while they may be expected to cope with general education, have no resources to cope with the problem of High or Technical and



[Shrimati Rathnabai Sreenivasa Rao.] Professional Education. If education becomes a concurrent subject, the Centre will have a scope for laying down certain uniform practices and establishing certain healthy standards!

DR. Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh): I do not want to make general observations about education. I think, on Friday we have a Private Member's Motion and we shall get opportunity to express our views on the problems of education in a general way.

I want to concentrate today on the question of Aligarh University and the implementation or enforcement of the Aligarh University Act. You will remember, I was one of those persons who supported that Act. I stated that it was essential that in all educational institutions, communal trends or communalism, whether by the majority community or the minority community, should be curbed and we should give more and more emphasis or orientation to education in the secular direction.

\*1 P.M.

Obviously, the main idea in my mind was that both in the Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University there have been, in the past, communal trends or communal forces of a reactionary character which have been trying to give a peculiar communal orientation to the educational system there and trying to dominate those institutions. Really we wanted an Act or a Constitution Order for those universities which would effectively curb communal tendencies. At the same time, I remember I requested the hon. Education Minister that it would be better to refer the Bill to a Select Committee because, as you know, Aligarh is a very sensitive spot and whatever laws you make about Aligarh, there was bound to be a lot of noise about them and it would be better to give an opportunity to the various points of view to be expressed in the Select Committee and ultimately come to a consensus. But at that time the hon. Education Minister was in a little hurry. I can understand that because we were pressurising him to bring an Act quickly. Seven years had passed and there was no constitution for the university. The university was governed from here and, therefore, we felt that it would be better to go through

the enactment quickly. Looking back, I think it would have been wiser to refer the Bill to a Select Committee. I say this because the Aligarh Muslim University Act has created a situation in which we find that we are not yet in a position to implement that Act. I have been appointed a Member of the Court but I have not yet had an opportunity of attending a meeting of the Court; it has not been possible to call a meeting of the Court. Cum: Upon some technical reasons.

And the reaction that the Act has created, the impact that it has created on the minds of the people who are deeply and culturally attached to the Aligarh Muslim University has been tremendous. It has been an outburst, and would assess that outburst in my own way—subject to objection—but it has created a powerful impact for good or bad—and widespread opposition to that Act has come into existence.

The Aligarh Muslim University has been traditionally a university with which the Muslim community has been deeply connected—connected emotionally and culturally—because it was the centre—as I stated in my earlier speech—of Indo-Muslim culture. It was, I would say, for a number of years the centre of Indo-Muslim culture. Scholars and students from all parts of India—not only from the North but from the South also—even from the extreme South—came to the Aligarh Muslim University. Not only the educated class but the mass of the Muslim population considered it to be a valuable seat of learning which preserved and safeguarded their cultural heritage and their place in the composite culture of India. Now, I think, we should have been a little more careful about it.

What is happening now?—An impression has been created throughout the country that this Act serves to wipe out the traditional and cultural character of this university, that it has sought to "annihilate that centre, to eliminate that centre and to create, in due course of time, a university which will be like any other university where not only in respect of internal management of the university or the governance of the university but in all other matters it would have no specific character of its own, no historic character of its own. And, therefore, the Muslims

at large have begun to feel, the overwhelming majority of Muslims feel that they will lose something which is precious to them. Now, I would not like this impression to be created. I think in a democratic State like India we have to preserve certain cultural values. We have to be careful about the cultural values particular of minorities and in a democracy, in a secular State due attention has to be paid to the problems of the minorities, their susceptibilities and their legitimate demands. If an impression is spread round that Aligarh University is to be annihilated, I think it would be wrong. It would harm us. It would harm our democratic life. It would antagonise the vast Muslims who today should normally come into the mainstream of our national life, who should be integrated with the rest of the country and who should be detached from their earlier communal background. They should feel that in this big country marching hand in hand with the other communities, that their cultural life and their cultural values are preserved, that they have a centre of their own, that they are allowed to develop their culture and preserve their culture.

श्री ओउमप्रकाश त्यागी : बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अहमद साहब ।

DR. T. A. AHMAD: I do not want your remarks. I heard everything patiently. You should listen to me with patience. I do not agree with those who in the name of secularism want to protect Hindu communalism. I do not want to encourage those who in the name of secularism want to protect Islam. I want real protection for the minorities so that the minorities may get integrated with the growing, common life of the majority and minorities. That way we have to develop a common outlook and a common life. Now, if I am allowed a little more time and I would request you to give me a little more time, I would say that this Act needs to be amended and it should be amended. It may be asked: Will it not be a climb-down? Shall we not be placating Muslim communalism? Would we be climbing down before Muslim communalism if we amend the Act? No. After all we are in a demo-

cratic State. We pass laws. We also see what impact those laws have on the minds of the people and how the people react. If there is an objection and if that objection is being utilised by reactionary elements against the growing progressive life of the country, then we have to pay attention to the situation in order to win over the better elements and isolate the reactionary and communal-minded Muslims from the vast people. We can carry out certain amendments and assure the vast mass of the Muslim population that their centre of learning, that their centre of culture is not being annihilated. It will be veiled and it should be duly protected. Nothing wrong in amending this Act. I tell you it would be useful if in this House. Minister later on puts forward some amendments which could be passed. There is nothing wrong in it. We go on amending so many laws. Now, in what directions I would like the Act to be amended? There are two aspects. One aspect is that of internal administration. I do think that the Act as it is makes the Vice-Chancellor much too powerful. The whole scheme looks nice on the face of it. I have gone through the note circulated by the Education Ministry where comparisons have been made in regard to the Aligarh University, the Banaras Hindu University, the Delhi University and all that. Superficially it would seem that this Act is quite good and a little more progressive from the point of view of internal administration. But in totality the checks and balances in this Act have been evolved in such a manner that ultimately it is the Vice-Chancellor and the Executive Council or I would say the Vice-Chancellor in Executive Council who becomes the supreme authority. I do not want to make any odious comparison. Then used to be the "Viceroy in Executive Council". I do not want to say that, but here the Vice-Chancellor in Executive Council becomes the supreme authority.

And since it is a Central University under the direct control of the Centre, ultimately it is the Central Government that overshadows it through the Vice-Chancellor. Analysed from that point of view, I think we have gone a bit too far. The democratic functioning and the internal autonomy of the university are quite precious. Shri Nurul Hasan is a professor of

[Dr. Z. A. Ahmad.]

outstanding merit and he would agree with an>one who says that the internal autonomy and the democratic functioning of the university should be preserved and fostered.

Now, you see the composition of the governing bodies. Start with the Court. The Court has been divested of its supreme authority. It was the supreme governing body. It ceases to be the supreme authority; it just discusses in a general way the functioning of the University, passes resolutions on the budget and all those sorts of things. It is no longer supreme.

Then the Executive Council has been constituted in a manner that most of its members will be directly or indirectly nominated by the Vice-Chancellor. The heads of departments do not rotate on the basis of seniority but on the recommendation of the Vice-Chancellor are appointed by the Executive Council. Then again if there is a Vice-Chancellor with bad intentions he can so function freely through the Executive Council, which now becomes the chief executive authority. He can constitute the Executive Council in such a manner that it will be entirely at his mercy. All powerful he becomes, and the Vice-Chancellor functions directly under the Central Government.

Therefore, I say that the checks and balances provided in the Act have to be looked into and examined to find out whether we can bring about any change in the distribution of the powers as between these various governing bodies. The existing checks and balances should be so changed as to give an assurance that it will not be one big boss sitting there with an Executive Council, who will rule over the whole university under the dictates of the Centre, with the internal democracy of the university and, in a large measure, the autonomy of the university not being there. I think that this situation should be looked into and examined. I am an old boy of Aligarh, and I feel very sorry that we have brought on the statute book into it something which has roused the indignation and opposition from all quarters. The university teachers are not satisfied for various reasons; the university students are not satisfied; the teaching staff is not satisfied and the non-

teaching staff are not satisfied. And most of the Muslims who send their boys to the university they are not satisfied.

SHRI B. 1. KEMPARAJ: Public are not satisfied.

DR. Z. A. AHMAD: This situation needs examination. We have created Students Councils. But have we not deliberately bypassed the Students Union? Normally in all the Universities it is the Students' Unions who traditionally, historically, become the organs of the students. Now a new body will be created and it is this new body of the Students Council which will, most probably, function in opposition to the Students' Union or perhaps the Students Union will be banned. I do not know what is ultimately going to be the pattern of the administration. You have, first, the Students Union and you have then the Students Council, a separate one. It means you will ban the Students Union. On the Students Council there will be nominated office-bearers and the Students Council will be represented on the Court. I think this smacks of lack of democracy. Whatever may be the present faults of the Students Union, they have to be given recognition; they have to be corrected. You cannot bypass the Students Union. The idea is to have a puppet body of the Vice-Chancellor which is to be represented on the Court. Therefore, the healthy aspect of the **Act**, the good aspect, that is, representation to the students on the Court is negated in a considerable measure by creating a new body in opposition to the Students Union and the Students Union will not get representation.

Now, Sir, so far as the non-teaching staff is concerned they do not *get* any representation. The teaching staff gets representation. That is a good aspect that you have introduced. If this is not done on the basis of seniority and the Vice-Chancellor does on appointing heads of department and these heads of department go to the Executive Council and they elect their representatives to the Court, then indirectly it is the Vice-Chancellor who will manage to keep his own men on the Court and on the Executive Council. This aspect also you have to re-examine.

There is another aspect, namely, the character of the University. When we passed the Aligarh Muslim University Bill, I think there was a demand here that representation should be given to all sorts of Muslim organisations. There were some amendment suggested here to that effect. At that time I opposed it. They wanted 40 to 50 people to be brought to the court from all sides to keep a certain balance in the University. I said at that time that representatives of some of these organisations would *not* be in tune with the character of modern secular educational institutions; they will not be mentally in tune. I now think that nothing will be lost if some of the organisations which are imparting instruction or education in Muslim learning, in Muslim philosophy in Muslim theology or in Arabic and Persian are represented on the court. I think some of these organisations may be given due representation. Let them be there. No Heavens will fall if some of them are given representation to create a sense of confidence among Muslims. I do not want them to be given very big representation because that is not in tune with the whole development that is taking place. Therefore, I will suggest that in the composition of the Court you should consider this question of giving representation to some of the Muslim educational institutions. I do not want representation to be given, for example, to what is called the Momin Biradari or any Biradari, as was suggested earlier. There was a suggestion that it should be given representation. I do not take this seriously. But some of the educational institutions like the one from which our Maulana Azad Madni comes should be given representation. It is doing good work among the Muslims in the sense that it is promoting their religious and cultural life. Such institutions are part of our life, part of India and part of the reality of the culture of Muslims. So organisations like that can be given representation. Nadwa of Lucknow can be given representation. Some other educational societies may be given representation. But I would not like Auqaf to be given representation. In principle it should also be conceded that Muslim learning should find its place on the court. Educational institutions which are connected with Muslim traditions, Muslim learning, Muslim philosophy, Muslim

theology, etc., should also find representation. Then, so far as old boys are concerned, well, it is all right. I do not oppose that. You have given ten members to old boys.

PROF. S, NURUL HASAN: Fifteen.

DR. Z. A. AHMAD: I think it is all right. I am an old boy. There will be other persons. Let them come. But regarding donors. I would say, no donors. So, in this way I would like the character of the University to be maintained. I definitely think that the hon. Minister of Education should bear in mind that the traditional character of the Aligarh Uni-has to be maintained in the context of the new secular education developing in our country. So when you nominate or select people, you should take care to see that the composition of the court is such that it inspires confidence. I do not want that this university should settle down to the communal ratio or the population ratio of 8:92. No. It has to be nursed as a specific institution with its own specific historical character. If there is a clear-cut understanding on that point, I think the Prime Minister or the Education Minister can state that. Also in the governance of the university, it should be borne in mind that the internal democracy and autonomous functioning of the uni-has to be strengthened and due amendments have to be made in its structure.

Lastly I would make an appeal to the hon. Minister. I am sure he is applying his mind to this question. I am sure he has already some changes in mind, and what the procedure should be, he may say that the amendments cannot be brought here, that the teaching staff can sit and decide. But I think it will have greater political impact if the amendments are brought here. You can sit in closed rooms and come to some understanding. But let it be clearly put before the two Houses; let a statement be made

[Dr. Z. A. Ahmad.]

that in view of the fact that there are certain misunderstandings, we want to clarify certain things, that we do not want to abolish the traditional character of this university and that we will maintain the character in the modern setting, and to that end amend the present Act.

Lastly I want to say a few words about Jamia. I think something should be done about the Jamia. It is not university according to the definition of university, What is it? it is a hybrid institution. Historically it has become a hybrid thing, Jamia should have its role in the field of higher learning. What specific role are you going to give it? I think you are not clear as to what role it will play. It is supposed to be under the Centre. The UGC does not come in yet. It is now proposed to bring it under the UGC. I think that will be good and I suggest that Jamia should be developed as a centre of Urdu learning. After all, Urdu is a language of India. It is not a language of Pakistan. We want a place where Urdu gets due recognition and gets scope for its development, where research work can be carried on in Urdu literature.

Jamia should be recognised as a centre of Urdu learning and research. And I would be glad if that specific role is assigned to Jamia. Let Jamia be brought under the UGC and let it be treated like any other University. And let it be properly run and not in an ad hoc manner. You have a representative sitting there with no fixed Budget, you go on changing the Budget from year to year, and that representative sitting there is an overlord and doing all type of wirepulling. No. I want it to be properly run with this role that it is recognised as a seat of Urdu learning and research. That is what I have to say. I hope the hon. Minister will give due attention to whatever I have said and accept my requests.

شری ایم۔ اسعد مدنی (اتر پردیش):

وائس چیرمین صاحب۔ ایجوکیشن اور تعلیم کسی بھی ملک اور قوم کے لئے ایک بنیادی طاقت ہے۔ اس سے ملک کے بسنے والوں کا ذہن اور ضمیر بنتا ہے اور انکے مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس سے ملک بڑھتا ہے طاقت پیدا ہوتی ہے اور روشنی آتی ہے۔ اس لئے وزارت تعلیم - ایجوکیشن منسٹری۔ ملک کی اہم ترین منسٹری ہے اور اگر کسی ملک میں اس منسٹری میں اندھیرا داخل ہو جائے تو پھر اس ملک کا کیا حشر ہوگا۔ یہ بہت بھیانک مستقبل کی نشان دہی کرتی ہے۔

آج ہمارے طلباء میں جس طرح کی انارکی - لوٹ مار کا روزانہ تشدد جلا دینا پھونک دینا شراب اور شہ ان برائیوں کی افراط اور بہتات لڑکیوں کو چھیڑنا۔ مسافروں کا باعزت سفر کرنا مشکل ہو جانا کوئی قانون مشکل سے نظر آتا ہے۔ کیا اس کا حشر ہونے والا ہے۔ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام کیسا کیریکٹر اور ذہن پیدا کر رہا ہے۔ کہاں ہم جائیں گے۔ اس طرف خدا جائے ہماری منسٹری کو توجہ ہے یا نہیں۔ پریشانی ہے یا نہیں۔ لیکن

ملک کو بہت دکھ اور پریشانی ہے۔ نہ کہیں صلاحیت نظر آتی ہے نہ اخلاق معلوم ہوتا ہے اور خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے جو کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ نیشنل انٹیگریشن کے خلاف بہت سی کتابیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ انگریزوں کی سازش سے جھوٹی لکھی ہوئی کتابیں جن سے اس ملک کے بسنے والوں کو نفرت لڑائی جھگڑا تنگ نظری کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ آج تک پڑھائی جا رہی ہیں اور پورے ملک میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ آزادی کے اتنے برسوں کے بعد بھی۔ ہماری منسٹری اتنا اہم بنیادی کام بھی نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارے اسکول ہمارے بچوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی کے نام پر انسان کی طرح دیکھنے کا قابل نہ چھوڑیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا بدگمانیوں اور دشمنیوں میں مبتلا کر دیں تو ان اداروں کو کیا کریں۔

یہ ہمارے ملک کو جہنم میں

لے جائیں گے۔ اس لئے وزارت کو ایسی تعلیم دینے والی کتابوں کو جرم قرار دینا چاہئے اور اس قسم کے لٹریچر کو روکا جائے۔ میرے سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا۔ میں بھی تقریباً اس سلسلہ میں ناٹید کرتا ہوں زوردار الفاظ میں۔ ہم لوگ کمیونلزم کے مخالف رہے اور اپنی قوم کا مقابلہ کیا۔ مصیبتیں اٹھائیں لیکن جو صورت حال پچھلے ایکٹ میں جو ابھی جاری ہے علی گڑھ کے ساتھ کی گئی ہے وہ بہت نامناسب ہیں۔ نہ اس میں کوئی ڈیموکریسی باقی رہی ہے نہ کوئی اٹونامی باقی رہی ہے۔ اگر تھی تو آج تک کورٹ کیوں نہیں بنی۔ وہاں کام کیوں نہیں ہوا۔ وہاں کوئی نمائندگی نہیں دی گئی۔ ایک ایسی ایسوسی ایشن کو مسلم ایجوکیشن کانفرنس جس نے اس کی بنیاد رکھی جس نے برطانیہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کیا۔ اس کو

یہی نمائندگی آپ نے اس سے  
نہیں دی۔ اس طرح سے آج  
وہاں کے طلباء سب کے سب  
پڑھار ہیں۔ وہاں کے پڑھانے والے  
ان کی اکثریت پڑھار ہے۔ جو نہ  
پڑھانے والا اسٹاف ہے اس کی  
بھی اکثریت پڑھار ہے۔ پولیس  
کے ہی۔ اے۔ سی کے بل پر آپ  
نے وہاں حکومت گم رکھی  
ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں  
نہ کوئی کمیٹی بنی نہ ایگزیکٹو  
کونسل کچھ نہیں بن سکا اس  
طریقہ سے اگر جمہوریت کی عزت  
مختم کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ  
اگر یہ ایکٹ ایسے ہی آسمان سے  
اترا ہے۔ دودھ جیسا دھلا ہے تو  
کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس  
مملکت کو تمام ملک میں باغ و بہار  
بنانا چاہئے تھا۔ کیا ہماری  
ایجوکیشن منسٹری کو ہمت ہے اس  
بات کی۔ تو کیا تاریخی اعلان کرنے  
کے باوجود وہ کچھ نہیں کر رہی  
ہے۔ دھوبی سے جیسے نہ گدھے  
کے کان اٹھتے۔ یہ صورت حال  
نہیں ہونی چاہئے۔ معاف دیجئے۔  
علی گڑھ یونیورسٹی سے مسلمانوں کا  
کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔

اس میں ہمارے غیر مسلم بھائی  
بہت بڑی تعداد میں بڑھے ہیں۔  
علی گڑھ یونیورسٹی میں بہت سے  
کچھ لوگ غلط بھی نکلے ہونگے۔  
لیکن وہاں سے ڈاکٹر ذاکر حسین  
اور رفیع احمد قدوائی جیسے لوگ  
بھی پیدا ہوئے ہیں۔ خود ڈاکٹر  
صاحب وہاں پیدا ہوئے۔ تمام ملک  
کی یونیورسٹیوں میں ہزاروں مسلمان  
بھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک ادارہ  
سے چونکہ جذباتی لگاؤ ہو گیا ہے  
اس لئے اس کو کھرچ کر پھینک  
دینے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا  
نہیں ہے۔ نہ کوئی جمہوری کردار  
رہے نہ تاریخی کردار رہے۔ سب  
ختم ہو گئے اور وہاں پارٹی کے  
وقار کو دھکا لگا ہوئے تم دوست  
جسکے دشمن اسکا آسمان کیوں ہو۔  
۱۹۵۱ کا ایکٹ پنڈت نہرو کی  
قیادت میں مولانا آزاد، ڈاکٹر ذاکر  
حسین اور اس طرح کے قومی رہنماؤں  
نے بیٹھ کر بنایا تھا ہو سکتا تھا  
اس کو معمولی ترمیموں سے نافذ  
کر دیا جاتا اور تمام جھنجھٹوں سے  
نکل جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا۔



اس طریقہ سے میں اتنی بات اور بھی عرض کرونگا کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جیسے بنارس کا ادارہ ہے یا گورونکل کانگری جن کی سندوں کو آزادی کے بعد مانا گیا ہے۔ حالت کا یہ تقاضہ ہے کہ وزارت تعلیم دارالعلوم دیوبند اور ایسے ہی جو دوسرے ادارے ہیں ان کی سندوں کو منظور کرے۔ ملک میں ایسے بہت سے ادارے ہیں جن کی سندوں کو آزادی کے پہلے اور آزادی کے بعد اسٹیٹ نے مانا ہے۔ اس لئے منسٹری اس مسئلہ پر غور کر کے مناسب اقدام کرے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔

اس منسٹری میں ایک آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ بھی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ کیا چیز ہے۔ تاریخی اہمیت رکھنے والی نواد کی حفاظت کرنا مقصود ہے یا ان کو بگاڑنا مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حفاظت کرنا مقصود ہے لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہیں واقعات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ہم بے الور اور بھرت پور میں معلوم کیا کہ وہاں پر مسجدوں مدرسوں اور درگاہوں کو نوڑ پھوڑ کر کے اسکول بنا لیا گیا۔ کوڑا گھر بنا

لیا گیا اور کہیں کہیں مندر بنا لیا گیا اور آپ کا ڈیپارٹمنٹ بالکل خاموش ہے۔ ہمیں دہلی میں قلعہ یگم کی مسجد میں ۱۹۴۷ تک نماز جماعت کا انتظام تھا اور وہاں کسی قسم کی پابندی نہیں تھی لیکن ۱۹۴۷ کے بعد کڑی ہو گئی اور وہ انتظام نہیں رہا اس کے لئے ہم برسوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں ایک بس اسٹینڈ بن گیا ہے اور بس اسٹینڈ بن جانے کی وجہ سے جو ہزاروں مسلمان وہاں آتے ہیں وہ اس کی ویرانگی کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خراب حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ اس میں کبھی کوئی جانور گھس جاتا ہے کبھی کوئی چلا جاتا ہے۔

श्री महावीर त्यागी : यह कहाँ है।

شری ایم۔ اسعد مدنی : یہیں دہلی میں کشمیری گیٹ کی طرف ہے۔

श्री महावीर त्यागी : उस जगह का नाम क्या है।

شری ایم۔ سعد مدنی : ہندو  
مسجد میں کہہ رہا ہوں۔ نو اس  
میں کبھی کوئی گدھا گھس جاتا ہے  
کبھی کتا گھس جاتا ہے۔ ہم اس  
میں نماز کی اجازت چاہتے ہیں اور  
اس کے لئے بار بار درخواست کی گئی  
لیکن آپ کا آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ  
یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں  
نماز پڑھنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔  
ہزاروں لوگ اس بات کی گواہ ہیں  
کہ وہاں نماز پڑھی جا چکی ہے۔  
لیکن وہ لوگ اس سے انکار کرتے  
ہیں۔

اس طرح سے اردو بورڈ کا مسئلہ  
ہے۔ سنا ہے کہ اس پلان میں ایک  
کروڑ روپیہ اس کے لئے رکھا گیا  
تھا۔ کیا کام ہو رہا ہے کیا  
نہیں ہو رہا ہے یہ ہمیں  
معلوم نہیں ہے۔ ہم کو یہ ضرور  
خطرہ ہے کہ شاید آ رہی سے زیادہ  
رقم لپٹس ہو جائے گی اور کہنے  
کے لئے ہو جائے گا کہ ہم نے تو رقم  
رکھی تھی۔ اس سلسلہ میں جو  
صورت حال وزارت تعلیم کی ہے وہ  
بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس

صورت حال کو بدلنا چاہئے اور  
روشنی آنی چاہئے اور اگر روشنی  
ہمیں آنی ہے تو کم سے کم اندھیرا  
نہیں آنا چاہئے۔ اگر اندھیرا وزارت  
تعلیم پھیلانے کی تو ملک میں کہاں  
سے روشنی آئیگی۔ اس لئے ہم  
چاہتے ہیں کہ اس اندھیرا کو بدل  
کر اس کی جگہ روشنی پھیلانی جائے۔  
ملک میں جن باتوں سے بے اطمینانی  
ہو سکتی ہے تو ان کی طرف توجہ  
دلانا ہمارا فرض ہے۔ بہر حال میں  
امید کرنا ہوں کہ ان کمزوریوں کو  
ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی  
اصلاح کی جائیگی کیوں کہ ملک کا  
سارا مستقبل وزارت تعلیم کے صحیح  
ہونے پر موقوف ہے۔

جن باتوں کی طرف میں نے توجہ  
دلانی ان کے بارے میں اگر ریکارڈ کی  
ضرورت ہوگی تو میں اس کو پیش  
کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ان مجمل  
الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو  
ختم کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں  
کہ آج جو موجودہ رخ ہے اس  
کو وزارت تعلیم بدلے گی۔

†[श्री एम० असद भदनी (उत्तर प्रदेश) :  
बाइस चैयरमेन साहब । एजुकेशन और  
तालीम किसी भी मुल्क और कोम के  
लिये एक बुनियादी ताकत है। इससे  
मुल्क के बसने वालों का जहन और जमीर  
बनता है और उनके मुस्तकबिल की  
तामीर होती है, इसी से मुल्क बढ़ता  
है, ताकत पैदा होती है और रोशनी  
आती है। इसलिये बजारत तालीम  
एजुकेशन मिनिस्ट्री मुल्क की अहमतरीन  
मिनिस्ट्री है और अगर किसी मुल्क  
में इस मिनिस्ट्री में अंधेरा दाखिल हो  
जाये तो फिर उस मुल्क का क्या हशर  
होगा? यह बहुत भयानक मुस्तकबिल  
की निशानदेही करती है।

आज हमारे तुलबा में जिस तरह  
की अनारकी, लूटमार का रोजाना तशदद  
जला देना, फूक देना शराब और नशा इन  
बुराइयों की अफरात बहुतायत लड़कियों  
को छेड़ना, मुसाफिरो का बाइज्जत सफर  
करना मुश्किल हो जाना, कोई कानून  
मुश्किल से नजर आता है। क्या  
इसका हशर होने वाला है, हमारे मुल्क  
का तालीमी नजाम कैसा करेक्टर  
और जहन पैदा कर रहा है, कहाँ  
हम जायेंगे। इस तरफ खुदा जाने  
हमारी मिनिस्ट्री को तवज्जोह है या  
नहीं, परेशानी है या नहीं। लेकिन मुल्क  
को बहुत दुःख और परेशानी है। न  
कहीं सलायत नजर आती है न अखलाक  
मालूम होता है और खराबियाँ बढ़ती  
चली जा रही हैं। इस तरह से जो  
किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं उनमें  
बहुत सी खराबियाँ हैं—नेशनल इंटेग्रेशन  
के खिलाफ बहुत सी किताबें पूरे मुल्क  
में फैली हुई हैं और पढ़ाई जा रही हैं।  
अंग्रेजों की साजिश से शूठी लिखी हुई  
किताबें जिनसे इस मुल्क के बसने वालों  
को नफरत, लड़ाई भगड़ा, तुनक नजरी  
के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है

†[ ] Hindi transliteration.

वे आज तक पढ़ाई जा रही हैं और  
पूरे मुल्क में पढ़ाई जा रही हैं, आजादी  
के इतने बरसों के बाद भी। हमारी मिनिस्ट्री  
इतना अहम बुनियादी काम भी नहीं  
कर सकी। अगर हमारे स्कूल हमारे  
बच्चों को हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,  
पारसी के नाम पर इन्सान की तरह  
देखने के काबिल न छोड़ें और आपस में  
लड़ाई भगड़ा, बदगुमानियाँ और दुश्मनियों  
में मुबतला कर दें तो उन अदारों  
का क्या करें। ये हमारे मुल्क को  
जहन्नुम में ले जायेंगे। इसलिए बजारत  
को ऐसी तालीम देने वाली किताबें  
को ज़ुर्म-करार देना चाहिए और  
इस किस्म के लिटरेचर को रोका जाये।

मेरे से पहले अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के  
बारे में डाक्टर साहब ने बहुत कुछ  
कह दिया मैं भी तकरीबन इस सिलसिले  
में तारीद करता हूँ जोरदार अलफाज में।  
हम लोग कम्युनलिज्म के मुखालिफ रहे  
और अपनी कोम का मुकाबला किया,  
मुसीबतें उठाई लेकिन जो सूरत हाल पिछले  
एकट में जो अभी जारा है अलीगढ़  
के साथ की गई है वह बहुत नामुनासिब  
है। न इसमें कोई डेमोक्रेसी बांकी  
रही है न कोई आटोनामी बांकी रही है।  
अगर थी तो आज तक कोर्ट क्यों नहीं  
बनी? वहाँ काम क्यों नहीं हुआ?  
वहाँ कोई नुमायंदगी नहीं दी गई।  
एक ऐसी एसोसियेशन को मुस्लिम येजुकेशन-  
नल कानफ्रेंस जिसने इसकी बुनियाद  
रखी जिसने बरतानिया गवर्नमेंट और  
गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मुतालबा किया।  
इसको भी नुमायंदगी आपने इसमें नहीं दी  
इसी तरह से आज वहाँ के तुलना सब के  
सब बेजार हैं। जो न पढ़ाने वाला स्टाफ है  
उसकी भी अक्तरियत बेजार है। पुलिस के  
पी-ए-सी के बिल पर आपने वहाँ हकूमत कर  
रखी है इसका नतीजा है कि वहाँ न कोई  
कमेटी बनी न एग्जीक्यूटिव काउंसिल

[ श्री एम० असद मदनी ]

कुछ नहीं बन सकी इस तरीके से अगर जमहूरियत की इज्जत खत्म कर दी। मैं कहता हूँ कि अगर यह एक्ट ऐसे ही आसमान से उतरा है, दूध जैसा धुला है तो क्यों तकलीफ हो रही है इस सलतनत को तमाम मुल्क में बाग ब बहार बनाना चाहिए था। क्या हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को हिम्मत है इस बात की। तो क्या तारीखी एलान करने के बावजूद वह कुछ नहीं कर पा रही है। घोबी से जीते न गधे के कान एंठे। यह सूरतहाल नहीं होनी चाहिए। माफ कीजिये—अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुसलमानों का कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इसमें हमारे गैर-मुस्लिम भाई बहुत बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत से कुछ लोग गलत भी निकले होंगे लेकिन वहां से डाक्टर जाकिर हुसैन और रफी अहमद किदवाई जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। खुद डाक्टर साहब वहां पैदा हुए। तमाम मुल्क की यूनिवर्सिटियों में हजारों मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक अदारा से चूँकि जज्बाती लगाव हो गया है इसलिये इसको खूब कर फेंक दें यह मसला हल होने वाला नहीं है। न कोई जम्हूरी करदार रहे न तारीखी करदार रहे। सब खत्म हो गये और वहां पार्टी के बकार को धक्का लगा। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। 1951 का एक्ट पंडित नेहरू की कैयादत में मौलाना आजाद डा० जाकिर हुसैन और इसी तरह के कौमी रहनुमाओं ने बैठ कर बनाया था। हो सकता था इसीको मामूली तरकीमों से नाफज कर दिया जाता और तमाम शंखों से निकल जाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इसी तरीके से मैं इतनी बात और भी अर्ज करूँगा कि बहुत से ऐसे अदारे हैं जैसे बनारस का अदारा है या गुरुकुल कांगड़ी जिनकी सनदों को आजादी के बाद माना गया है। हालात का यह तकाजा है कि वजारते तालीम दारुल उलूम देवबंद और ऐसे ही जो दूसरे अदारे हैं उनकी सनदों को मंजूर करे। मुल्क में ऐसे बहुत से अदारे हैं जिनकी सनदों को आजादी के पहले और आजादी के बाद स्टेट ने माना है। इसलिए मिनिस्ट्री इस मसला पर गौर करके मुनासिब अकदाम करे। इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा।

इस मिनिस्ट्री में एक आरक्योलाजीकल डिपार्टमेंट भी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह आरक्योलाजीकल डिपार्टमेंट क्या चीज है? तारीखी अहमीयत रखने नवादर की हिफाजत करना मकसूद है या इनको बिगाड़ना मकसूद है। आप कहते हैं कि हिफाजत करना मकसूद है लेकिन जहां तक हमारी मालूमात हैं वाक्यात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हमने अलवर और भरतपुर में मालूम किया कि वहां पर मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को तोड़ फोड़ करके स्कूल बना लिया गया। कूड़ा घर बना लिया गया और कहीं कहीं मन्दिर बना लिया गया और आपका डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश है। यहीं दिल्ली में कुदसीया बेगम की मस्जिद में 1947 तक नमाज जमायत का इंतजाम था और वहां किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी लेकिन 1947 के बाद गड़बड़ी हो गई और वह इंतजाम नहीं रहा। इसके लिये हम बरसों से कोशिश कर रहे हैं। वहां एक बस स्टैंड बन गया है और बस स्टैंड बन जाने की वजह से जो हजारों मुसलमान वहां आते हैं वे इसकी वीरानगी को देखते हैं और वे यह भी देखते हैं कि यह किस तरह से खराब हालत में पड़ी हुई है।

इसमें कभी कोई जानवर घुस जाता है कभी कोई चला जाता है।

श्री महावीर त्यागी : यह कहां है ?

श्री एम० असअद मवनी : यहीं दिल्ली में कश्मीरी गेट की तरफ है।

श्री महावीर त्यागी : उस जगह का नाम क्या है ?

श्री एम० असअद मवनी : मैं कुदसीया मस्जिद कह रहा हूं, तो इसमें कभी कोई गधा घुस जाता है, कभी कुत्ता घुस जाता है। हम इसमें नमाज की इजाजत चाहते हैं और इसके लिये बार बार दरखास्त की गई लेकिन आपका आरक्ष्योलाजीकल डिपार्टमेंट यह कहता है कि हमारे पास वहां नमाज पढ़ने का कोई रिकार्ड नहीं है। हजारों लोग इस बात के गवाह हैं कि वहां नमाज पढ़ी जा चुकी है लेकिन वे लोग इससे इंकार करते हैं।

इस तरह से उर्दू बोर्ड का मसला है। सुना है कि इस प्लान में एक करोड़ रुपया इसके लिये रखा गया था। क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह हमें मालूम नहीं है। हमको यह जरूर खतरा है कि शायद आधी से ज्यादा रकम लेप्स हो जायेगी और कहने के लिये हो जायेगा कि हमने तो रकम रखी थी। इस सिलसिले में जो सूरतहाल वज्जारत तालीम की है वह बहुत ही अफसोसनाक है। इस सूरतहाल को बदलना चाहिये और रोशनी आनी चाहिए और अगर रोशनी नहीं आती है तो कम से कम अन्धेरा नहीं आना चाहिए। अगर अन्धेरा वज्जारत तालीम फैलायेगी तो मुल्क में कहां से रोशनी आयेगी। इसलिये हम चाहते हैं कि इस अन्धेरे को बदल कर इसकी

जगह रोशनी फैलाई जाये। मुल्क में जिन बातों से वेइतमिनानी हो सकती है तो उनकी तरफ तवज्जह दिवाना हमारा फर्ज है। बेइतहाल में उम्मीद करता हूं कि इन कमजोरियों को ठीक करने की कोशिश की जायेगी असलाह की जायेगी क्योंकि मुल्क का सारा मुस्तकविल वज्जारत तालीम के सही होने पर मौकूफ है।

जिन बातों की तरफ मैंने तवज्जह दिलाई उनके बारे में अगर रिकार्ड की जरूरत होगी तो मैं इसको पेश करने के लिये तैयार हूं। इन मुजमिल अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो मौजूदा रख है इसको वज्जारत तालीम बदलेगी।

SHRI M. RUTHNASWAMY (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, may I begin by wondering why the Department of Education and Social Welfare, over which the honourable Minister of Education so genially preside-, is called the Department of Education and Social Welfare when I see ven few items of social welfare within his jurisdiction? It is only according to this Report, reporting the activities . . .

PROF. S. NURUL HASAN: Sir, I would like to make one correction. The document that the honourable Member is referring to is the Report of the Department of Education and the Department of Culture. The Report of the Department of Social Welfare is of light blue colour and this has also been supplied to all the honourable Members. Apparently, he has not got it.

SHRI M. RUTHNASWAMY: I am saying that the Ministry is called the Ministry of Education and Social Welfare.

PROF. S. NURUL HASAN: We have brought our Report in two volumes.

SHRI M. RUTHNASWAMY: There are WW items of social welfare mentioned in this report, namely, youth welfare and sports and adult education.

[Ref. M. Ruthnaswamy.]

Adult education is no doubt a very important factor in social welfare. But the progress made in adult education is very halting and hesitating in this country. When you see that twenty years after independence only 30% of the people are literate and the rate of growth of literacy is only one per cent per year, you can realise how backward adult education is. A new device has been found and it is what is called functional literacy. One would think that it is a new discovery of the Education Ministry. But every system of effective education has to take into account the function, the environment and the background of the people who are to be made literate. Thus the agricultural community would be educated from the standpoint of and taking into account the background of the farmers, the cultivators and the farm labourers who are engaged in agriculture. But let us see what the growth of functional literacy has been. So far, about 80 districts have been taken into account in this movement and this Report promises that another 20 districts will be brought under this scheme in the coming year and the annual output of this functional literacy movement is one hundred and eighty thousand per year. At this rate, in view of the fact that the farming population, not only the farmers, but also the lease-holders and the farm labourers, constitute about 100 million of our population, it will take nearly a hundred years for this functional literacy scheme to bring about the literacy of even the farming population. So, a more vigorous system has to be discovered and one has been brought to the notice of the Ministry of Education and that is the Venkata Rao method of making adult people literate. This method has been invented by a veteran worker in the adult education field and it is claimed that it will make an adult literate within a space of three months at a cost of Rs. 20 per head.

I am very glad and am thankful to the Ministry of Education for making the first step towards the encouragement of this method. Recently, the Ministry of Education, under his leadership, has sanctioned a certain amount of money to be supplemented by the Government of Andhra Pradesh. Now, Mr. Venkata Rao has

gone to the district of Nizamabad in Andhra Pradesh and has begun his work. At least I am looking forward to the results of that movement. That movement is successful. I would recommend this method most enthusiastically to the Minister of Education and his Ministry.

The other social welfare, with which this Ministry is connected, is the youth welfare and sports. This is very properly in the jurisdiction of the Ministry of Education. In connection with sports, I like to bring to the notice of the Minister of Education the fact that there has been a kind of scandal recently in the appointment of the new manager who accompanied the Indian Hockey Team to take part in international movements. The gentleman who has been associated as manager with the Indian Hockey Team for years, was substituted by a police officer, the morale of the hockey team can be sustained abroad with a new officer being appointed just on the eve of its departure from India? I hope the Minister of Education will look into this matter and right the wrong if it has been committed.

These are the few remarks that I would like to make, Mr. Vice-Chairman, and I hope that the recommendations that I have made in this short speech will be pathetically considered by the Ministry to be able to take the steps that are necessary to encourage this movement of literacy, because that is the foundation of political and social progress. Unless the people are literate, how are they going to come progressive not only in the field of economy but also in the field of social progress?

I hope and trust that the Minister will take up this movement of adult literacy as one of the chief movements with which his Ministry will be concerned during the term of his office.

SHRIMATI SUSHILA SHANKAR ADVAREKAR (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, many of the hon. Members have spoken more on the educational aspect, but I would like to deal with the social welfare aspect of the Ministry.

Although the Social Welfare Ministry can take justifiable satisfaction in the extremely good work it has done in the last more

tian 20 years, we still feel that the Ministry will have to again gear itself up to play an important role in the Fifth Plan period. The Department will now have to promote many new activities to meet the challenges of the seventies. If we fail to do so, it means we are still less aware of the ramifications and intricacies of these challenges.

The system of social welfare services which has been achieved till today is high the standard of its time, but it is not at all comprehensive and adequate to meet the multifarious problems and needs of the country. This system has grown up at different speeds and with different patterns. The impetus came either from some pressing need or some visionary idea, rather than a set plan. But, Sir, now we will have to work to achieve a balanced economic growth and social justice for the society. The Ministry will definitely play a role in making people ready to accept the new technology, new science and even the new way of life without making them lose their feet off the ground. And in order to achieve that, the machinery to reach the remotest villages and backward and weaker section of people will have to be evolved. The network of social welfare boards all over the country will have to be remodelled. It should work as a dynamic agency to meet the social needs. It just cannot be a meeting point for worker and community, but it must be a strong force which can weld them together, which can integrate them together for national integrity and progress. Social work workers must adjust to developing philosophies of social work and also to changing professional knowledge and skills. Work should be given the highest importance. In solving the problems of the weaker sections of the society who constitute the majority in the country.

The concept of social work and methods are not static, as they continuously develop. Social work, Sir, can really supply a field laboratory and it can tremendously help in breaking down the class distinctions and help in establishing certain standards and values. But it requires coordination and cooperation at all levels. To give an example, Sir, I would like to mention one or two cases. What happened to the Bulsara Committee Field

Counselling Service to help and guide voluntary organisations? What is the future of condensed courses for self-employment for economically handicapped people and whether any evaluation of such scheme has been done to find out whether it has served any purpose?

It is an accepted fact that evaluation is a scientific investigation to judge the efficiency of a programme in terms of its objectives and achievements. Do we do that? Help for people's individual and personal difficulties call for expert skills, especially in a welfare state. Have we tried to make available such expert knowledge and skill for the use of the agencies who require it? Related to this is the practice and training of social welfare workers. As the functions and problems have differentiated and multiplied, it is very necessary to provide this facility. The very purpose of social welfare services is to make them available in an effective way to the society. It is a well-accepted fact that along with the Government Agencies, private voluntary agencies are indispensable to work in this field. The time has come now that not only we have to extend these immensely, but we have to execute them skillfully. And this requires more social workers and a continuous effort to increase their potential competence and then alone the organised social welfare work will be elevated to a position of great importance.

Efforts will have to be made to achieve greater effectiveness through periodic reappraisal and reformulation of guiding principles. The field of social welfare is undergoing a continuous development and diversification into specialized areas. Thus Research has become a recognised part of our social endeavours.

The Indian society is being churned from torn. A small humble villager also aspires to be something, life everywhere is moving. In such a critical time, every individual needs some help. He is to be made aware and conscious of the sacrifices and adjustments he has to make for the betterment of the society. I may be permitted to cite an instance. As part of the Gandhi Centenary Programme, the Maharashtra Government had announced that villages doing outstanding



[Shrimati Sushila Shankar Adivarekar.]  
social work. More than 5,000 villages participated in the competition. Out of them, there is a wide different picture. I visited some of these villages to understand the motivation behind their progress. I realised the importance of highly stimulated social action. Is it not possible that 5 lakh and odd villages in our country could be made to feel that they have a task to fulfil and face the challenges of modernisation? Can we not build up an appropriate mechanism for motivating people to act together for their social upliftment? Let farming and productive activities get dovetailed into the

social and human side of life. The most of the programmes are stereotyped, working with the same slow tempo. They benefit the richer sections among the backward people and the less fortunate are left out of the pale. This will require new programming and a change in the attitudes of the Social Welfare Ministry. Is it too much to expect the Social Welfare Ministry to devise ways and means to bring in this new transformation with all the rich experience that they have over more than two decades? And I am more than confident that the Social Welfare Ministry will recast its approach to the problems that we are facing today rather than come on its activities with the same old policy.

Sir, I sincerely feel that the time has come when social welfare is given the maximum importance in order to achieve our twin objectives of eradicating poverty and fighting social injustice.

Thank you.

SHRI G. A. UTHAN (Tamil Nadu):  
Mr. Vice-Chairman, Sir, you might remember that Prof. Nurul Hasan's appointment as a Minister of Education was announced when we were not in session. I was one of the very few who believed whether or not, that took the Government's interest, pride and happiness in this appointment.

SHRI M. RUTHNASWAMY: Why do you say that?

SHRI G. A. APPAN: Whatever it is, that is what I feel. You might also be aware that when his budget was discussed for the first time, I paid great ovation and encomium. Not only myself but there were others also who were happy over it. I am having my hats off for his proficiency

in the field of education, from the perspective of the Government. I have seen in him a Minister I am pained to see that whatever we spoke on the floor of the House to guide him or just to guide our own experience—not to guide him because he is not very high! I am pained to see our experiences, our views, our suggestions were not properly heeded to. Some of the views I pointed out here.

Everyone's mother tongue is sacred to him; it is dear to him, to her as well. In the field of education one could understand things better and get better education if it is through one's own mother tongue. Nobody can deny that and if

the languages scheduled in the Constitution of India are to be developed, the humble view is that each language should be left to its own self. For people who are jealous to protect their own mother tongue and to benefit it, it should support and work for its improvement at his own cost but not one language to be supported and improved or developed or encouraged at the expense of the other languages. I had been a member of the Consultative Committee

of Education and Social Services. You know the Constitution provides in the Directive Principles of the State policy should be free at least up to 11 years of age, at least up to 8th standard, if I am not incorrect. Everybody wants to develop his own language but on a number of times both on the floor of this House and on the platform of the Consultative Committee I requested the Minister to please satisfy the greatest aspiration of not the majority but the minority in the Andaman and Nicobar Islands. Mr. Vice-Chairman, I have some of his plans. He wants to give top priority or very high priority for the development of Urdu within a short time. I have been in the office. I do not deny that I do not object to it. You can develop any language to any extent, like Hindi, Bengali or Bengali. I should not care to give education at least up to the 8th standard for the families in the Andaman and Nicobar Islands. Eight or ten times I have made representations. I have written to him. I have written to the Deputy Minister. I have written the Minister. I have written to the Home Minister. In spite of that still

unrest ami this much of non unrest. We ba'e seen h even in the elc-ediicar.in standard, even al the middle school level and also til the high school level. Why? Please pardon me. As a leather I say, I have been a i from my early years, I have been a leather in an elementary, school, in a middle school, in a high school ami in the training school. But l io work from si\ in the morning iii! very late in the night. Teaching is a missionary job, it should be laken in a missionary spirit, reaching cannot be taken by a

who loves nifiui, loves leisure. No doubt, leaching has a great leisure provided we an able to do our duty dutifully and utilise the spare lime. How nt.i.u.v of the present-day teachers are true to their jobsi I sav, not many, except in the private!] managed schools, lint lo! this Gov- ciuniciiii uanis to (tub all the private- management schools and aided which help noi themselves but the Government, by running the institutions more effectively, in i refined and disciplined

nh luic efficiency at hall the time, grant, mainicnano wants i,, give them all hardships.

Ii is paying iis teachers because they are able to agitate, because the, are able to beausi they are able to give trouble to the Government. But because the private school managers are vet

because ihew' are not sullu i<m-. ed, Ihev do not taie. There is a I in at ion Bill which the lion. Minis- tei is going to pilot. Of course, I have told him: " nit the school mana- gers who have experience. But do not try to kill the goose that lays the golden The new Bill that they are going to intro-

biti killing iln lays the golden egg noi one goose but a number of goose, i request the lion. Mi- see that he abandons l lie Bill or tli.u In- gels tie »c or views of private managements.

sir. I entirely ague with Prof. Kulhna- vva in remarks, I like them. I was doing adult education even with I. anbach's Chart. ;li that I was able to make people was in my high school career. In our days only high shool students from the missionary institutions used io take up that work. Government did : any attention to aduh education

unrest ami this much of non unrest.  
We ba'e seen h even in the elc-ediicar.in  
standard, even al the middle school level and  
also til the high school level. Why? Please  
pardon me. As a leather I say, I have  
been a i from my early years, I have been a leather  
in an elementary, school, in a middle  
school, in a high school ami in the  
training school. But I io work from si\ in the  
morning iii! very late in the night. Teaching is a  
missionary job, it should be laken in a  
missionary spirit, reaching cannot be taken  
by a

who loves nifiu, loves leisure. No doubt, leaching has a great leisure provided we an able to do our duty dutifully and utilise the spare lime. How nt. iuv of the present-day teachers are true to their jobs! I sav, not many, except in the private!] managed schools, lint lo! this Gov- ciunicii uanis to (tub all the private- management schools and aided which help noi themselves but the Government, by running the institutions more effectively, in i refined and disciplined

nh luic efficiency at hall the time, grant,  
mainicnawants i,, give them all  
hardships.

It is paying its teachers because they are able to agitate, because they are able to because they are able to give trouble to the Government. But because the private school managers are vet

because ihev'are not sullu i<m-  
ed, Ihev do not taie. There is a  
I in at ion Bill which the lion. Minis-  
tei is going to pilot. Of course, I have  
told him: " nit the school mana-  
gers who have experience. But do not try to  
kill the goose that lays the golden The new Bill that  
they are going to intro-

lays the golden egg noi one goose but a  
number of goose, i request the lion. Mi-  
see that he abandons l lie  
Bill or tli.u In- gels tie »c or  
views of private managements.

sir. I entirely agree with Prof. Kulhna-  
 vva in remarks, I like them. I was doing  
 adult education even with I. an bach's Chart.  
 ;li that I was able to make people  
 was in my high school  
 career. In our days only high shool stu-  
 dents from the missionary institutions used  
 io take up that work. Government did  
 : any attention to aduh education

[Sim G. A. Appan.] in those days. When I was in the high school and in the teachers' training school, I used to go out (lining lile week-ends and take up adult education co .....ss through Mr. Khaitan and Mr. Lorbcer of Pasumalai, the architect of the Kallar Reclamation scheme and of adult education, stalwarts in those days. I agree with Prof. Ruthna-swamy. The Hyderabad Plan could be done uTid implemented within three months. \ person could he made literate within 5 months within a cost of Rs. 20. I think the cost factor may nol be correct. If you want cheap things, it will not be worthwhile. But ii is possible to make a person literate within 3 months, Ai the rate of Rs. 20 a month, it will cost Rs. 60 per head. Let every teacher take l(1 people every month or 20 people. So lei us have j band or aiuv of people who will take up addi education as a missionary vice; rather than keeping and retaining people upto 60 years you retire people at 55. Let the teachers take to adult education and be paid the same salary. I feel undue encouragement is being given to people with good merit. There is a proposal in the Fifth Vile Year Plan for merit scholarship. But many a time these schO' larships are given to \erv rich people. This scholarship is a grant, an aid given to alleviate the sufferings of the parents. A number of officers drawing Rs. 2,000 O) Rs. 1,500 per month have come and complained to me that their son gets his scholarship onl) at the end of March.

SURI PITAMBER DAS: so that the) get it three months in advance?

SHRI (J. A. APPAN: No, ii is at the end of the fear. To whom should the loan scholarship be given? Please do not any scholarship to anybody who can manage without it. Urn do give financial assistance to those who waul it bill nol as a dole at the poor man's eosl. Let boys who are talented and who want to return the scholarship money be given scholarship. This would be in (lie interest of the nation, in the larger inti let them repa) when the) get employed. *dune lift! rings.*) "two minutes. Why do you throw away money on those who do noi Ar--, rve ii i Live loan i.> | fhi \ will i< turn ii when the) come back and get employment. VV'hen they cami

here give them main nee, nol Rs. 2,000. Lei ii be recovered. Our coun- nv is not a rich country. Ministers should not dole out money. I entirely agree with Riilliu aswamv dial our education should be job-Oriented, preferably agri culture-oriented. India being mainly an agricultural countr) oui education should be agriculture-oriented, What is the use of turning out people aimlessly? What is the D SI nl turning out a matriculate, turn ing mil ;i r.t.'.C. a graduate or a post graduate and what not? We should have the cosl factor in mind and how ii is utili sed. When a person invests money in thousands be does expect interest from it. Is ii not (he duty of the Education Mi- nisiiv to see that the money spent on edu cation should be usefully spent; No doubt ii is social seii free. But ii cannot be frittered away.

J UK VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): I hat will do.

SHRI (J. A. APPAN: Only two or three minutes.

I III. VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Vim have already taken more time. We are getting late. There aie oilu-i speakers also. You have already taken 18 mini.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन् पांच बजे गये हैं। अब कल इसको लीजियेगा। पांच बजे से आगे चलाने के लिए न बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने कुछ कहा है और न लीडर आफ द हाउस ने कोई अनुरोध किया है।

श्री सीताराम सिंह : श्रीमन्, इसको कल के लिए रखा जाय।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आज इसको आगे चलाने की क्या आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू): आज ही खत्म किया जायगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अभी बहुत से बोलने वाले हैं और अभी मंत्री महोदय का जवाब होना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : आज ही समाप्त होना है।

श्री महावीर त्यागी : इसके अलावा हाउस में मंत्री महोदय का तब जवाब होना चाहिये जब कि ज्यादा से ज्यादा लोग हों।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हाउस में कोई है ही नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : आज का बिजनेस आज ही खत्म करना है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आज अभी बिजनेस बहुत है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : कभी-कभी पांच बजे के पहले भी हाउस ऐडजर्न हो जाता है। परसों पांच बजे के पहले ऐडजर्न हो गया था।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अभी बहुत से बोलने वाले पड़े हैं जो घंटों बोलते हैं। फिर आज ही समाप्त करने की क्या जरूरत है।

डा० जेड० ए० अहमद : सब थक गये हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कल के लिए रखियेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : मिनिस्ट्री के बारे में जब कभी चर्चा हुई है पहले भी तो उसी दिन वह समाप्त हो गयी है। एक घंटे ज्यादा बैठने से क्या हो जायगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक घंटे में यह नहीं होगा।

SHRI RANBIR SINGH (Hanana): Another resolution is coming up on the non-official day. VVe can finish the discussion now. The Minister can reply tomorrow.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अभी बहुत से बोलने वाले हैं। समय नहीं है तो क्या जरूरत है। किसी भी कीमत पर यह आज समाप्त नहीं हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी -

SHRI A. G. KULKARNI: We have t\* the ivdrk to-day.

SHRI OM MEHTA: It has been (tedded already. One day is always given for this purpose.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : पांच बजे के बाद फिर क्यों बैठ रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : इसमें खास बात यह है कि इस को पांच बजे के पहले खत्म हो जाना चाहिए था। एजेंडा पर कम स्पीकर्स थे, लेकिन अधिक स्पीकर्स को मौका दिया गया यह सोच कर कि कुछ ज्यादा देर तक बैठ जायेंगे Let us not break the tradition.

Mill; OM MEHTA: We are prepared to close the discussion if they are not inte-I in the reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Yes, Mr. Barbora.

S] [RI G. A. UTAN: Onlv two n points, Sir. [have taken only ten tninu

HIV. VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): No. )ou have taken 18 minutes.

-SHRI (... A. APPAN: Only two more points,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): All right, JfOU can take two minutes more.

SHRI G. A. APPAN: Mr. Vice-Chairman, I have been idling the House and the Government that elementary education is Bore import an I for the country than higher education. Those who can afford go in Cor higher education but in i

lucation there is no use massing 83 en Hi students in Standard I. I request the lion. Minister to consider this ver\ important suggestion, In Standard I and Standard II the strength should no) be

than 25 or 90 pa class. Otherwise it will not be a class, it will lie only a gang, and our money will be wasted. How (an a teachei manage more than 2u oi

(iits- Al least 70 per (( in money spent on education should go for elementary education up to Standard VJII. He should also see thai all children within the school-going age are brought to the school. II parents do not semi then ien, we should | iiie parents and

H children below 11 years of age into I he field of education.

1 111. VI(i CHAIRMAN (SHRI \. B. lit, thank you.

SHRI G. A. APPAN: Regarding Sche duled Castes and Scheduled Tribes, you arte nor able in admit Scheduled Castes people up to 20 per cent though the Con stitution provides for it. Yon should make it a point ■ rant for am school, collegt "i professional insiitution. win i her ii is under private man i or it. is a Government institution, unless this quota of 20 per cent for tlit-Scheduled Castes and , I pi i (cm lor the Scheduled Tribes is fulfilled.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. II. RAJU): Now, please sit down. Mr. Barbara.

SHRI G. A. APPAN: I hope the lion. lo do lull jUSt 'he salient i hat I have raised, fthank you.

श्री गोलाप बरबोरा (आमाम) :

उपमभापति जी, आजादी के 25 साल के बाद भी शिक्षा मंत्रालय के सामने न तो कोई दिशा है और न कोई उनका प्लान है। जैसा कि आज सुबह प्रमइमरी एजुकेशन के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि 1961 ई० से ले कर 1971 ई० तक जो निरक्षर लोगो की सख्या इस देश में 333 मिलियन थी, वह 386 मिलियन तक बढ़ गई। यह हालत है हमारे देश में। और जो शिक्षा मंत्रालय ह उसमें न जाने कितनी शाखाये हैं, समझाना मुश्किल है। तो इसकी वजह क्या है ? वजह यही है कि आप सोचते हैं पुराने ढंग से कि सब जगह स्कूल हो, स्कूल बिल्डिंग हो, दो ढाई सौ रुपये महीने की तनख्वाह वाला टीचर हो, तभी आप एलिमेंटरी एजुकेशन को स्ट्रेड कर पायेंगे। यह होना तो असम्भव है और आप जितना भी प्लान करते जायेंगे उतना हो इस देश में, इस मंत्रालय के गलत तरीके की वजह में, निरक्षर लोगो की तादाद और बढ़ती जायगी। मेरा यह सुझाव है कि जल्दी से जल्दी देश में एक शिक्षा मेना दल कायम करना चाहिये, जिसमें एजुकेटेड अन-इम्ब्लायड नौजवान हो और उनको कुछ मेनटेनेंस एलाउस दिया जाय या कुछ पाकेट मनी दे कर के स्कूल कालेज के विद्यार्थियों को वालटरी काम करने का मौका दिया जाय। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाय करीब पांच लाख लोगो का पांच लाख गावों के लिये। इसके पीछे आपका बहुत ज्यादा रुपया खर्चा नहीं होगा। तो ऐसा प्रोग्राम ले कर के काम करे। यह प्रोग्राम और देशों में भी हुआ है, चाइना में हुआ है और यूरोप के दूसरे देशों में हुआ है रूस में हुआ है सन् 1917 की क्रान्ति के बाद। आप अगर इसी खयाल में रहेंगे

कि आपका बजट प्राविजन हो, उस बजट में एलिमेंटरी एजुकेशन के लिये कुछ ग्रांट हों, हर जगह कम से कम पांच हजार रुपये की एक स्कूल बिल्डिंग बनवायें और उसमें परमिनेंट टीचर एम्पाईट करें तो आपका देश में सभी लोगों को एलिमेंटरी एजुकेशन देने का सपना कभी पूरा नहीं हो पायेगा।

इसी के साथ-साथ जहां हायर एजुकेशन का सवाल है, वहां चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कोई डिस्प्लिन नहीं है, कहीं कोई युनिफार्म पालिसी नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन की वही हालत है, कालेज की वही हालत है और आपकी युनिवर्सिटीज की भी वही हालत है। आपकी सेंट्रल युनिवर्सिटीज है, जैसे कि दिल्ली में सेंट्रल युनिवर्सिटी है। अगर दिल्ली की युनिवर्सिटी सेंट्रल युनिवर्सिटी है तो हर युनिवर्सिटी के आने वाले विद्यार्थियों को यहां मौका मिलना चाहिये लेकिन वह नहीं मिलता है। जो आसाम के रहने वाले हैं, जो वहां के विद्यार्थी हैं उनको मौका नहीं मिलता है। वहां गौहाटी और डिब्रूगढ़ युनिवर्सिटी है और चूंकि गौहाटी और डिब्रूगढ़ युनिवर्सिटी का रिजल्ट कुछ देर से निकलता है तो जब दिल्ली युनिवर्सिटी में या यहां जितने कालेज हैं उनमें जो विद्यार्थी वहां से एडमिशन के लिये आते हैं तो सीट्स फुल रहती हैं और उनको एडमिशन नहीं मिलता है। इसको सेंट्रल युनिवर्सिटी हम तभी मान सकते हैं जब कि जिस शहर में वह हो या उसके अगल बगल जो हों उनको ही मौका नहीं मिले, बल्कि उसमें हर प्रान्त के लोगों को पढ़ने का मौका मिले। तो इसके लिये कोई युनिफार्म पालिसी आपकी होनी चाहिये।

युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हर युनिवर्सिटी को पैसा देता है, हर कालेज

को पैसा देना है लेकिन युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रुपये को ले कर— ज्यादातर कांग्रेस के लोग—धोखली मचा रखी है। एक तो ऐसा हो गया है कि पावर में आने के लिये, इलेक्शन मशीनरी में कुछ कब्जा पाने के लिये, लोकल लीडरशिप में काबू पाने के लिए कोई भी स्टेट में कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, वह अपना आदमी हर कालेज की गवर्निंग बाडी में रखता है और लोग खा जाते हैं पैसा।

मैं जिस शहर से आता हूं उसके कालेज का डेड दो लाख रुपया गायब है, युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का वह रुपया है। वहां एक क्लर्क गए, एक प्रिन्सिपल साहब गए, ठीक है, लेकिन वहां का कांग्रेस का एक नेता था जो आसाम का मिनिस्टर है और एक कभी एम० एल० ए० रहा, वे लोग भी वहां थे। पांच साल तक लगातार कोई आडिट नहीं हुआ और प्रिन्सिपल साहब गए, वहां का कोई पीयन चला गया, एक क्लर्क चला गया, लेकिन जो नेता लोग थे उस गवर्निंग बाडी में, जो चाहे जाने हों, अनजाने हों, उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जहां कालेजों में युनिवर्सिटियों में रुपया देता हो, उस रुपए का इस्तेमाल किस ढंग से होता है, उस पर भी नजर होनी चाहिए, और ठीक ढंग में अगर उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो ऐसे कालेजों में पैसा तब तक नहीं देना चाहिए, जब तक उसके खर्च का सही इस्तेमाल करने के बारे में कोई रिपोर्ट उनको न मिले।

आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ "यूनिसेफ" "यूनेस्को" आदि संस्थाओं का भी संबंध है। आपको यूनाइटेड नेशन्स की संस्थाओं के जरिए करीब 6-7 करोड़ रुपया आया होगा और उनमें से एक

[श्री गोलाब बरबोरा]

संस्था इन्टरनेशनल कमीशन फार कोऑप-  
रेशन विद यूनेस्को भी एक है। उसमें  
चिन्तने फैलोशिप्स हैं, कितने कर्मागन्म  
हैं, ग्रान्ट्स फार फारेन टैवलर्स हैं।  
लेकिन हम देखते हैं—मंत्री महोदय  
आप बुरा मत मानिए—ये सब जितने  
फैलोशिप्स ग्रान्ट्स और कमीशन जो हैं  
ये सब आफिसेज बने हुए हैं दिल्ली  
के इन्-गिने और यह लोगों के कमाने  
खाने का और भाई-भतीजावाद बढ़ाने  
के साधन है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसकी  
जांच होनी चाहिए।

श्री गोलाब बरबोरा : जरूर इसकी  
जांच होनी चाहिए। वही हालत एके-  
डेमीज की है। वह चाहे संगीत नाटक  
अकाडमी हो, ललित कला अकाडमी हो,  
साहित्य कला अकाडमी है। मैं एक  
पिछड़े हुए प्रदेश का वासी हूँ, मेरा  
चिन्तेज है कि इन सारी फैलोशिप्स में,  
सब कमेटियों में, कांसिले में, इन्स्टी-  
ट्यूशन्स में, मेरे प्रान्त में किसी को  
मोका मिला है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता  
है। हमारे यहां भी शिक्षित लोग  
हैं, हमारे यहां भी स्कालर लोग हैं,  
उनको क्यों चान्स नहीं मिलता है?  
या तो कलकत्ता के रीजनल आफिस  
के इन्-गिने लोग या मद्रास के रीजनल  
आफिस के इन्-गिने कुछ लोग भाई-भती-  
जावाद चलाते हैं। इसके कैसेज आए  
हैं। आपके पहले इम्पीरियल गैजे-  
टियर या इम्पीरियल गैजेटियर के बाद  
नेशनल गैजेटियर में कुछ प्रबन्ध हुआ  
था, जब हुमायुन कबिर साहब एजुकेशन  
मिनिस्टर थे, सन् 1958 में कोई कमेटी  
बनी, 4 वाल्यूम निकालने को तय  
करके एक वाल्यूम कहीं 1971 में  
छपा, एक प्रेस में गया, और एक  
ओई तैयार है, प्रेस में गया नहीं है,

और चौथा अभी तैयार नहीं है, लाखों  
रुपए खर्च हुए इन सब पर—आडिटर  
जनरल का रिमार्क है—तो मैं जानना  
चाहता हूँ आप क्या कार्यवाही उस  
पर कर रहे हैं? वह एक वाल्यूम भी  
इस रंग का है कि वहाँ एक बहुत पुरा-  
ना जो इम्पीरियल गैजेटियर ब्रिटिश  
जमाने का रहा उसी को फिर रिप्रिन्ट  
किया गया। तो नेशनल गैजेटियर  
बनाने में या डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर बनाने  
के लिए जो व्यवस्थाएँ हैं, उसमें लाखों  
करोड़ों रु० जो खर्चा करते हैं, उसके  
जरिए काम क्या हुआ या नहीं, इसकी  
देखभाल करने की भी क्या कभी आप  
कोशिश करने हैं? मेरा तो खयाल  
है कि इसके ऊपर देखभाल करने वाला  
कोई है नहीं।

स्पोर्ट्स का जिक्र किया गया। ओल-  
म्पिक गेम्स में जो कुछ भी हुआ था  
देश भर को मालूम है। हिन्दुस्तान में  
स्पोर्ट्स भी उसी तरह कुछ लोगों के  
हाथ का एक खिलाता बन गया है,  
पेशा बन गया है और आप जानते हैं,  
इस देश की एक बीमारी है, विदेश  
धूमने के लिए लोग बड़े लालायित रहते  
हैं। ओलम्पिक्स एसोसिएशन में लोग  
घुस जाते हैं, जिनका खेल-कूद के साथ  
कोई संबंध नहीं होता है। सब कोई  
विदेश जाना चाहते हैं। अभी जब  
पार्लियामेन्ट की रीसेस हुई थी तो  
किमी ने लिखा था—इंडिया इज कलड  
फ्राम एक्साइड बिकाउज आन्मोस्ट द इन्डा-  
यन कैबिनेट इज घाउट आफ इंडिया।  
वही मिनिस्टर्स की हालत है, वही  
आफिसरों की हालत है और वही देश के  
जनसाधारण नागरिकों की हालत है।  
कलकत्ते के एक लेखक ने अपने उपन्यास में  
लिखा है कि बहुत से ऐसे हिन्दुस्तानी हमारे  
देश में आज हैं जो विदेश जाने के इच्छुक हैं।  
और विदेशी ट्रांजिस्टर और दूसरा सामान

पाने के लिए वे अपने देश को भी बेच सकते हैं। इस तरह की बीमारी हमारे हिन्दुस्तान में है और वही बीमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी है। कहीं पर उसने के मिशन बना दिये हैं, कहीं पर कमेटी बना दी है, कहीं पर फैलोशिप कायम कर दिया है और एकाडमीज बना दी हैं। स्पोर्ट में भी इसी तरह की व्यवस्था है और देखने में यह आया है कि इस देश में सब विभागों में इस तरह की चीज बना दी गई है। इस तरह की जो व्यवस्था और भावना है उसको हमें रोकना चाहिए।

दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मैं तो यह चाहता हूँ कि इस तरह के केवल दिल्ली में ही न हों, बल्कि हिन्दुस्तान के हर प्रान्त में इस तरह के क्लब होने चाहिए और हर रीजन में इस तरह के क्लब होने चाहिए।

आज हिन्दुस्तान के लोगों में यह भावना हो गई है कि पंजाब के ही लोग अच्छे हाकी के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन हाकी का सबसे अच्छा खिलाड़ी बिहार का एक आदीवासी निकला है। दिल्ली में हाकी का जो मैच हुआ था उसमें आसाम, (मिजोरम), की टीम आई और उनको पंजाब की मशहूर टीम के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें खेल ड्रा रहा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ इन सब लोगों को मौका बहुत कम मिलता है। आपने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि सब कौंसिल में ही फंस जाते हैं। इस्प्रिन्ट इवैन्ट्स में नागालैण्ड के नौजवानों, वहाँ के विद्यार्थियों को भी ट्रेनिंग की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे लोग भी हिन्दुस्तान के और लोगों के मुकाबले में आ सकें। आज वहाँ के लोगों को इस तरह के खेलों और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता है। आज हमारे देश में विदेशों में धूमने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है और इस प्रवृत्ति का असर यह हुआ कि चाहे कोई भी संस्था

हो, स्पोर्ट्स की संस्था हो या कोई दूसरी संस्था हो, सब विदेशों में धूमना चाहते हैं, चाहे उनका उस चीज से कोई सम्बन्ध न हो।

सरकार की ओर से फुटबाल के खेल के लिए लाखों रुपया मिलता है, लेकिन आज हम यह देखते हैं कि यह खेल भी पहिले के मुकाबले में गिरता जा रहा है। आज हम यह भी देखते हैं कि हमारे हाकी के खेल का भी स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है और इस तरह से दूसरे खेलों में भी हमारा स्टैंडर्ड गिर गया है। आज इन संस्थाओं में भाई-भतीजेवाद की भावना फैल गई है।

(Interruption). इस तरह की संस्थाओं में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई है। आसाम और जो बार्डर के क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को इन संस्थाओं में जगह नहीं मिलती है और न ही उनको किसी तरह की कोई सहायता मिलती है।

एक चीज में यह अर्ज करता चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रीय गाने की ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रान्तों में संस्थाएं खोली हैं। क्या आप राष्ट्रीय गाने को सब प्रान्तों में गवाना नहीं चाहते हैं? आप को सब प्रान्तों में इस तरह की संस्था खोलनी चाहिए।

इसी तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कूलों में मील्स देने की स्कीम है और इसके बैनीफिसियरिज 127.40 लाख लोग ही हैं। यह स्कीम 19 स्टेटों और यूनियन टैरिटरीज में लागू है, लेकिन आसाम अरुणाचल, मेघालय जैसे स्टेटों में लागू नहीं है और न ही लिस्ट में इन स्टेटों का नाम है। स्कूल मील्स सब बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि सब देश के बच्चों को न दिया जा सके, परन्तु हर प्रान्त के कुछ जिलों में यह स्कीम तो लागू की जा सकती है।

इसी तरह से आपके यहाँ प्रान्तीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की और



[श्री गोलाप बरबोरा]

मौलिक पुस्तक छापने की व्यवस्था है। आपने एक नेशनल बुक ट्रस्ट बनाया है और उसके कर्मचारी दिल्ली में आज भी हड़ताल में है। वहाँ पर किताबों का ट्रान्सलेशन होता है और इसी तरह से आपने साहित्यिक अकादमी की स्थापना की है। हमारे यहाँ से लोकसभा के जो सदस्य हैं वे उसके सदस्य हैं। वे शासक दल के हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी ट्रान्सलेशन किया जाता है, किताब छपी जाती है, अनुवाद किया जाता है वह रीजनल लेंग्वेज में बहुत कम किया जाता है। आप मौलिक किताबों को तामिल, आसामीज और दूसरी रीजनल भाषाओं में अनुवाद करवाइये।

मेरे एक मित्र हैं आसाम के अजीत कुमार शर्मा, प्रोफेसर, उनको कहा गया था प्लेटो रिपब्लिक का तर्जुमा करने के लिए। उन्होंने उसका तर्जुमा करके भेज दिया। फिर यहाँ से किसी को देखने के लिए भेजा गया, लेकिन फिर भी आज तक वह किताब छपी नहीं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में आया है कि कई किताबें लेकर बाद में उनको वापस कर देते हैं। उन्हें क्यों लिया जाता है और फिर बाद में वापस किया जाता है? इसके पीछे क्या है?

इन सब चीजों पर मंत्री महोदय जवाब दें और जहाँ तक हो सके इस अन्याय को रोकने की व्यवस्था करें तो देश में शिक्षा की भी तरक्की होगी और आम तौर से हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा।

श्री सीता राम सिंह (बिहार) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक शिक्षा नीति का सवाल है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुर्दा वही है फकत कफन बदल गया है। हकीकत यह है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज अंग्रेजियत अपने देश में जोर-शोर से बढ़ रही है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीलाद छोड़ गए।

श्री सीता राम सिंह : मुझे पता नहीं है किसकी कौन श्रीलाद है, इसके लिए अनुसंधान करना पड़ेगा। आज इस देश में कुछ लोग अपने बच्चों को मम्मी और डैडी सिखलाते हैं, माता और पिता शब्द से उन्हें सक्त नफरत है।

श्री गोलाप बरबोरा : अपने घर में अंग्रेजी में बोलते हैं दिल्ली में।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आपको पता नहीं है, हसन साहब हिन्दी समिति में अंग्रेजी में बोलते हैं।

श्री सीता राम सिंह : यह खासियत है अपने देश की। एक बच्चे पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ 26 वर्षों की आजादी के बाद गलत शिक्षा नीति के चलते इस देश में 38 करोड़ 60 लाख अनपढ़ हैं। एक तरफ सेंट जेवियर जैसे पबलिक स्कूल चल रहे हैं, दूसरी तरफ बेसिक प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जहाँ धान रोपना, छँती बनाना—इसकी तालीम दी जाती है। एक तरफ शासक वर्ग पैदा किया जाता है और दूसरी तरफ शासित वर्ग पैदा किया जाता है और डोल पीटा जाता है समाजवाद का। समाजवाद का अर्थ क्या होता है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह नई परिभाषा है।

श्री सीता राम सिंह : जिस देश में शिक्षा में भी एकरूपता न हो—आर्थिक विषमता की बात तो दूर रही—उस देश का शासक वर्ग यह डोल पीटे कि हमारे देश में समाजवाद आ रहा है, यह जनता के साथ

एक क्रूर मजाक है राष्ट्र के साथ धोखा है, बेईमानी है।

श्री कल्याण चन्द : जैसे आपने समाजवाद का नाम लिया और प्रिवी पर्स में साथ दिया।

श्री सीता राम सिंह : प्रिवी पर्स किसने दिया था, यह भी बता दो। प्रिवी पर्स तुम्हारे ही नेता लोगों ने दिया था। हम हमेशा से इस बात के विरोधी थे कि प्रिवी पर्स दिया जाय।

(Interruption)

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : आप बोलिए आपका समय कम है।

श्री सीता राम सिंह : श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। ये लोग राक्षसी बहुमत के बल पर मचल रहे हैं, लेकिन वह दिन भी आने वाला है जब यह नहीं रहेगा।

श्री कल्याण चन्द : वह दिन नहीं आएगा।

श्री सीता राम सिंह : यह दुनिया परिवर्तनशील है, इसको मित्रों याद रखो।

महोदय, इस देश में जब तक शिक्षा में एकरूपता नहीं आयेगी तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता है। महोदय, मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि शिक्षा में वह ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे भंगी की सन्तान हो, शिक्षा एक समान देने की योजना बनायेंगे? जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक महोदय मेरा विश्वास है कि देश नहीं बनेगा, राष्ट्र नहीं बनेगा क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति ज्ञान अर्जन के लिए नहीं है, वह नौकरी के लिए और व्यापार के लिए है।

महोदय, शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। लेकिन आज इस शिक्षा पद्धति से हो रहा है सर्वनाश। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बुनियादी तौर से शिक्षा नीति में तब्दीली करें, परिवर्तन करें और उसे जनसुखा बनायें।

दूसरी बात यह कि आर्थिक विषमता के चलते, इस देश में अनेक बच्चे शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक विषमता का जहाँ तक सवाल है आज इस देश में अनेकों ऐसे गांव हैं जहाँ स्कूल में सर्वगं हिन्दू उच्च जाति के बच्चे हरिजन, आदिवासियों के बच्चों को अपने साथ नहीं बैठने देते। उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। उसकी एक मिसाल मैं बताना चाहता हूँ। बिहार के वैशाली जिले में एक महुआ प्रखंड है। वहाँ के मिडिल स्कूल में एक हरिजन शिक्षक सर्वगं शिक्षक के गिलास से पानी पी रहा था और उसके मुँह से गिलास छीन लिया और मारने की धमकी दी। इतना भयभीत किया गया कि वह हरिजन शिक्षक उस स्कूल से ट्रांसफर करवाकर दूसरे स्कूल में चला गया है। इस घटना की सूचना मैंने राज्यपाल को दी, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं सका है और जो उच्च वर्ग के शिक्षा अधिकारी हैं वह हरिजन शिक्षक को धमकी देते हैं कि अगर तुम समझौता नहीं करते हो तो तुमको हम डिसमिस कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हरिजन मिनिस्टर के साथ भी ऐसा हो रहा है?

श्री सीताराम सिंह : मिनिस्टर तो मुँह देखने के लिए हैं। यह विषमता का सवाल है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो हरिजन शिक्षक हैं उनके साथ इस तरह की घटनायें घटती हैं तो जो गरीब

[श्री सीताराम सिंह]

हरिजन के बच्चे हैं उनका क्या होता होगा। आज यह हकीकत हो गई है।

(Interruption)

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय साक्षरता सेना का तुरन्त गठन किया जाए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो पढ़े लिखे लोग बेकार हैं उनको रोजी भी मिलेगी और दूसरी बात यह कि जो अपने देश में एक करोड़ लोग अनपढ़ हैं वह साक्षर भी हो जायेंगे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि शिक्षा की जो पद्धति है उसमें विद्यार्थियों को छठी या सातवीं कक्षा तक पढ़ाई के अनुसार उसके दिमाग की जांच होनी चाहिए और जिस विद्यार्थी को जिस विषय की अभिरुचि हो उसको उसका विशेषज्ञ बनाना चाहिए। उनको दूसरी किताबों का बोझा डालकर उसके माथे पर उनका भार नहीं डालना चाहिए। सभी कुछ सम्भव कल्याण हो सकता है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : भोजन की व्यवस्था भी कराइये।

श्री सीताराम सिंह : महोदय, गांधी जी ने कहा था कि जब तक इस देश में देशी भाषाओं में राजकाज नहीं चलेगा तब तक इस देश की आजादी अधूरी रहेगी। इस देश का शासक वर्ग गांधी जी को अपनी सत्ता के नशे में भूल गया है।

उप-सभाध्यक्ष (श्री श्री० बी० राजू) : धन तो हो गया होगा।

(Time bell rings.)

श्री सीताराम सिंह : श्रीमन्, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है बिल्कुल व्यापारिक ढंग से यह शिक्षा चलाई जा रही है। जहाँ तक पाठ्यपुस्तकों का सवाल है, आज देखा जाता है कि अच्छे से अच्छे लेखक

की जो किताबें हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और आज जिन का सम्पर्क, जिनका सम्बन्ध शिक्षा मंत्रालय से है वे चाहे जितनी भी घटिया किस्म की किताब लिखें, टेक्सट बुक कमेटी में उनकी किताब चल जाती है। (Interruption) यह सेंटर की बात मैं नहीं कहता। यह पूरे देश की बात है।

मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जो मैंने एक दो सुझाव रखे हैं उनके सामने उनपर वे ध्यान दें और शिक्षा को बुनियादी तौर से तब्दील करें क्योंकि आज बड़े लोगों के लड़के पांच सौ सात सौ और एक हजार रुपया माहवार खर्च करते हैं, लेकिन जो गरीब का बेटा है उसके लिए कौन सा इन्तजाम हो रहा है। 26 वर्ष की आजादी के बाद भी उसके पढ़ने लिखने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है जबकि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनके अनुसार हर नागरिक बराबर है। यह संविधान में है लेकिन व्यवहार में इसकी उलटी बात चल रही है।

THE MINISTER OF EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I would like to express my deep sense of gratitude to (he hon. Members for the concern I find they have shown about various educational matters facing the country. Before I take up individual points, I would like to state that I find myself in agreement with most of the suggestions which have been given by the hon. Members and, therefore, if I am unable to comment on every point that has been raised, I would not like my hon. friends to feel that their valuable suggestions will not be taken due note of. I am looking at the clock because I can see that most of my friends are also looking at the clock and, therefore, I shall try to be as brief as possible.

Sir, the most important point which has been raised, in my opinion, is the question of liquidation of illiteracy. Mr.

colleague has already made certain observations in the morning and I would not like to repeat those points. But, as generally indicated, the strategy which the Education Ministry is advocating to the State Governments is that first of all we must ensure that there is 100 per cent

enrolment of children in the age group of 6-11 within this Five Year period. Second-

Ministry must ensure that within the Sixth Plan period we are able to cover the age group of 11-14 so that the Directive Principles are implemented. Then, side by side with this we want to give the next highest priority to the age group 15-25, the young people who should have been given education if the Directive had been implemented by 1960. But unfortunately we were unable to implement this Directive Principle and I do not think there can be any difference of opinion that it is one of the most important of the Directive Principles and it should have been implemented. And, therefore, I can only join my hon. friends here in expressing my deep sense of anguish that we were unable, as a nation, to implement this Directive Principle. It will therefore be the effort of my Ministry in concert with all the State Govern-

ments to ensure that this is implemented as soon as possible and, along with this, the

age group 15-25 is tackled with a determination so as to make up for the time that we have lost after 1960."

Then, naturally there are other programmes of literacy, for adults. Some reference has been made by hon. friends here but I would not make a comment on that at length. But I would like to submit, Sir, that for achieving these objectives we have been making different types of strategies, working out these strategies so that taking a realistic view of the situation, we are able to solve this problem. This is being done in a number of ways. Firstly, as the hon. Member would recall, the National Development Council has approved the Document prepared by the Planning Commission called "An Approach to the Fifth Five Year Plan". If that Document is examined it would be seen that this objective of 100 per cent enrolment in the age group 6-11 and 75 per cent enrolment in the age group 11-14 must be

achieved before the end of the Fifth Plan. It will also be observed by the hon. Members that out of the total outlay which has been provisionally proposed for the education sector, half has been allotted for elementary education and elementary education has been included in what is called, the minimum national needs programme of the country. Therefore, the fear that has been expressed, that elementary education is not being given either the financial backing or the importance, will be, I hope, proved to be unfounded. And my Ministry will be sparing no effort in seeing that these targets about which a national consensus has already emerged are achieved because these targets have been accepted by the Education Ministers of all the State Governments and then in the National Development Council by the Chief Ministers of all State Governments. I do not think there is any difference of opinion that these are very important targets and we must implement them. Now, within this framework we have been evolving various types of strategies. We realised, for example, that there are economic factors, factors of poverty, factors of social backwardness which have prevented children in the past from being enrolled in schools or, having been enrolled in schools, made them drop out. Now, this may be partly due to the inadequacy of the schools, but more often it is due to social and economic factors. In order to overcome this we are working out a whole scheme of informal education, part-time education and whole-time education, where schools cannot be established. For example, in very small villages where there are only a few houses, it may not be possible to have a full-fledged school. We are devising various other methods to ensure that education reaches all these children. We have also put forward the concept of community schools which will act as models and which will, hope, be multiplied as the general community sees the advantages in having schools of this type in which the parents get involved. Most of the parents are unfortunately still illiterate and, therefore the school's duty does not end merely with providing education to children. It should be also extended wherever possible, to the parents of the children. Then, there are various other types of

not only to inculcate a proper sense of values. I have accepted the national policies such as secularism, such as democratic way of life, such as socialism, such as abhorrence for such practices as untouchability, and a general humanising influence of education is absolutely vital. Along with this, I entirely agree that we have to remember the role of education in creating a healthy respect for our culture, for our basic values of culture. My friend, Mr. Tyagi, asked me to define what culture is. I would not attempt to do so because as he undoubtedly knows, no two academics will have the same definition of culture. When I was a student doing a paper on medieval Indian culture, we realised that in the whole class no two students had the same concept or definition of culture. So, I will not attempt to define it. But there are certain aspects of culture on which there can be no difference of opinion.

PROF. S. NURUL HASAN: Therefore, the basic values of Indian culture which are well understood, those must be inculcated through the educational system. Side by side with it, with our feet firmly planted in the mother earth of India, we must, as Gandhiji said, "allow the fresh breeze to enter from whichever it comes." We must encourage a scientific outlook and prepare our people to use science and technology as a m of culture without being, as Gandhiji said, 'blown off their feet.' This is easier said than done. We are conscious that these are the objectives. We are trying to bring about changes in the curricular, co-curricular and extracurricular activities in the schools. In fact, a working group of experts is trying to evolve prototypes of syllabus and of extracurricular and co-curricular activities. We hope that these will meet with the approval of the State Governments and that they will be able to implement them.

Sir, it has also been suggested by an hon. Member that the Education Ministry has failed to have those text books removed from the curriculum which militate against the basic concept of secularism or national integration. Sir, I am deeply conscious of the failure of my Ministry

for which I accept the fullest responsibility because you. Sir, in this House and in the other House have given *to* the Ministers a great deal of authority to see that their policies can be implemented. But, Sir, this happens to be one of the areas in which our failure is not as marked as it is in many other spheres. In the time of my distinguished predecessor, Prof. V. K. R. V. Rao, a working group was appointed to make a crash evaluation of the school textbooks in the most sensitive subjects. That work has been completed more or less. A very large number of textbooks were carefully examined. Some were found to be completely objectionable. Some were found to be partly objectionable while others were considered to be all right. The Kducation Ministry drew the attention of the State Governments to this report. I am very happy to submit, Sir, that in most cases the Education Ministries of the State Governments expressed their agreement with the comments that we had made and have promised that they would take the necessary action. In some cases action has already been taken. In other cases action is going to be taken. But we are confining our activities merely to pointing out the faults. We have also, through the National Council of Research and Training, set up groups which are preparing text books which, we hope, will satisfy the needs and urges of the people.

Sir, while I am on the subject of the textbooks I must express ray horror at the textbook which my distinguished hon'ble friend, Shri Sanyal, mentioned here. I took the liberty of going out to the lobby in order to have a good look at that book and I feel that Mr. Sanyal's words were perhaps not strong enough so far as that book is concerned. I will certainly do whatever lies in my power to see that that book and such other books are not inflicted on the Indian children.

Sir, I would like briefly to mention the question of sports before I go on to the question of the Aligarh Muslim University on which Dr. Ahmad has spoken. Sir, in the matter of sports we realise that the international competitions are held under the Olympic rules. Olympic rules

provide that the organisation of sports shall be with voluntary organisations not controlled by Government. Therefore, when there is a lack of control from the Government, it becomes a little embarrassing for the Government to do much about what these voluntary organisations are doing. In the case of the Manager of the Indian Hockey Team for the World Cup I am conscious of the fact that many distinguished hockey players like Mr. Dhyani Chaudhary, Mr. K. D. Singh 'Babu' have expressed their concern at the choice. So we have suggested to the All India Council of Sports, which is an expert body—which also has the other component of lay people but more than half of the members are experts—to hold discussions with the Indian Hockey Federation to see whether this matter can be settled in a manner which will be generally satisfactory to the country.

Sir, I would like to take some of your time and that of the House for a discussion of the Aligarh Muslim University. Sir, I must start by making a confession. From my early boyhood I have looked upon Dr. Ahmad as a political friend, philosopher and guide and I have not yet, Sir, got rid of that basic feeling.

As this House will recall, I tried my best to act on the advice which many hon. friends, including Dr. Ahmad, gave before the Aligarh Muslim University Bill was brought before this House, and Dr. Ahmad was generous enough to make a reference to it. I would repeat that the suggestions which he has given are given and will be given the fullest and the most careful consideration by Government. Sir, I would like to make two or three points in this respect. Firstly, the main demand which is being put forward regarding the amendment of the Act has centred round one specific demand which, I am afraid, the Government will not be able to accept and which, I am afraid, Dr. Ahmad will not be able to accept either, and that is that the preamble of the Act should be so amended as to declare that the Aligarh Muslim University is an institution established and administered by the Muslim minority of India in terms of article 30 of the Constitution. Sir, when I placed this Bill for the consideration of the House, 'I explained the Government's point of

[Prof. Nurul Hasan.] view at length, and except for probably one or two Members, there was general agreement that this demand could not be accepted. Therefore, I would like to make this point very clear. Now, if this point is made clear, then the question that arises is that, firstly, the country needs to be assured that the Aligarh Muslim University has a definite historical character and the Government will not and does not propose to alter that character. Sir, that assurance has been given repeatedly by the Prime Minister, by myself and by other members of the Government. I stated in the other House that the character of the University was defined in the original 1920 Act in the preamble. In section 4(1) of the Act, it is stated that the University will continue to perform the obligations of the Mohammedan Anglo-Oriental College. That has not been changed. Section 5(2) gave to the University a special responsibility of making provision for Islamic theology and learning.

That has not been altered. These sections remain in exactly the same form in which they were first enacted by the Central Legislature in 1920, and the Government have no intention of making any changes therein. Furthermore, as a result of the political campaigns that have been going on, it is being said that while the Government claims that this historical character has not been altered and will not be altered, it has in a reality that in the three basic policy-making bodies, the Court, the Academic Council and the Executive Council of the University, the Muslims have had, for historical and traditional reasons, a majority. Sir, we realise that the Muslims have had, for ical and traditional reasons, a majority, and the Government have no intention of bringing about changes so that this majority is artificially reduced to a minority. That is not the policy of the intention of the Government.

Then, Sir, I come to the specific points which Dr. Ahmad has raised. Firstly, he spoke of the internal administration of the University and made out the point that the Vice-Chancellor in Executive Council has become the supreme authority and the Central Government, through the Vice-Chancellor, overshadows the University.

Sir, I most respectfully beg to differ from the last part of it. No Vice-Chancellor, having been appointed, takes his orders from the Ministry of Education and, in fact, a Vice-Chancellor who were to agree to take his orders from the Ministry of Education would not be a fit person to be appointed as a Vice-Chancellor. But, Sir, I would like to clarify the other point that has been made by Dr. Ahmad. He has feeling that in the appointment of the Deans and the Heads of Departments, the Vice-Chancellor will have a good deal of voice and, therefore, it creates an impression although, in my opinion, it is unjustified, that the principal authorities of the Uni-

iversity are a nominated body. And, therefore, Sir, I am entirely in agreement with Dr. Ahmad that this system should be changed and the Dean and the Head should be either appointed on the basis of rotation or on some other objective criterion in which the subjective element of selection should not exist. Similarly, he made a reference to the Court and said that it had ceased to be the supreme governing body. Sir, unfortunately, I was not expecting this question to come up at such a length and, therefore, have not brought the documents with me, but I think I am quoting correctly. Sir, in the 1951 Act, the Court was declared to be the supreme governing body and was given the right to review the acts of the Executive and the Academic Council save where these Councils have acted in accordance with the powers given to them by the Act or the statutes. I think these are the precise words. Sir, if you examine the list of powers and functions given by the Act and the statutes to the Executive and the Academic Council, you would notice, Sir, that there is hardly anything of substance or significance to the functioning of the University which has been left out. Therefore, in no matter of significance could the Court review either the actions of the Executive Council or the actions of the Academic Council. Sir, in the Act which this House has been pleased to approve, it is stated that all important policy matters of the University can be reviewed by the Court. Sir, this, I would submit, is a point that perhaps has not been fully examined by my distinguished friend. Then, Sir, in regard to the Students' Council, he is

under the impression that the Students' Union has been bypassed. Sir, this again does not correspond to the facts. The President, the Vice-President and the Secretary of the Students' Union are the *ex-officio* members of the Court. But if an impression is going round that there is some attempt to have a nominated element—there is no nominated element—then, I am quite prepared to go along and say that the other members or at least half the members, apart from these office bearers of the Union and a few other categories, should be directly elected by the student community so that there is no feeling that the student community is being bypassed. And I would like to make this submission that till now there is no other University where students have been given so much representation on the court. And the court is not a mere debating society. Five of the 21 members of the Executive Council will be elected by the Court. And I therefore feel that there has been a great deal of misunderstanding about the Act and the statutes.

I hope that my honourable friends would try to clarify these points so that it does not lead to a hysteria being built up on the basis of misunderstanding. And I would repeat that many of the changes which have been suggested by Dr. Ahmad would be acceptable to the Government even in the matter of composition of the court, bringing in people representing Muslim culture and learning. We have an open mind on this. I have discussed this matter with the representatives of the staff association, and have indicated to the staff association that most of these demands and these matters are such on which the Government would be prepared to go along with the academic opinion and that I hope that the Executive Council would soon make the relevant changes in the statutes, and I will be quite prepared to advise the Visitor to accept those changes. I think that should meet most of the points which Dr. Ahmad has raised in this debate. I am most grateful to him for having done so. He has also referred to Jamia Milia and this matter has also been referred to by another honourable Member. There is no discrimination either for Jamia and against other institutions of higher learning or against Jamia and in favour of

other institutions; either way there is no discrimination. The difference in figures which were given out of grants was on the basis of the number of teaching departments, the functions that the institutions have been performing and the total enrolment. All those factors have to be taken into account in fixing the normal grant. One of the aims and objects of Jamia has been to impart instruction through the medium of Urdu. This it has been doing and the Government has been giving as much assistance as is possible in accordance with the norms that have been laid down. While I would like Jamia to increase its research output in Urdu, I would submit that Urdu is a language, as you quite correctly pointed out, of India and not of that part of the country which is now Pakistan. Therefore, it is but natural that our own people should take a great deal of interest in Urdu. I hope that not only this institution, but many other Universities, will be taking a greater interest than they have been taking. They have been taking a great deal of interest in research work in Urdu and imparting higher education in Urdu. I am subject to correction, if my memory does not fail me, the total number of persons studying Urdu in the other Universities of Uttar Pradesh is larger than the number in the Aligarh Muslim University and Jamia Milia put together. I am subject to correction, but this is my impression. Recently the Banaras Hindu University has decided to establish a separate Urdu Department in Banaras. Therefore, the development of Urdu is a programme in which we are all interested and it is not an interest which is confined to a particular community.

While I am referring to the language issue, I would like to make a specific reference to what Shri Appan said. In regard to the medium of instruction at the elementary stage, Government accept fully and wish to implement the provision in the Constitution. Article 851A lays down:

"It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities



[Prof. S. Nurul Hasan.] ties for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. . ."

In accordance with this broad policy, the Government of India would like to provide all the necessary facilities and in the cases of Andaman and Nicobar, we are conscious of the fact that there is a Tamil speaking minority which has every right to have its children educated through the medium of Tamil and I hope a decision will be taken soon in this regard.

Shri Appan is not here. But I would like to say that while we want to give support to every language of India, the Government of India have a special obligation under the Constitution in regard to Hindi and therefore you cannot blame us if we give far greater attention to the development and promotion of Hindi than to the other languages. It is not that we hold other languages to be unimportant. We consider them to be very, very important and we want to provide every facility for them to develop. But, Sir, Article 351 of the Constitution layi down:

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

This is a Constitutional obligation of the Central Government and the Central Government would be failing in its duty if it did not consider that the development of Hindi is one of the major tasks of the Ministry of Education.

SHRI KRISHAN KANT : May I put one small question to the hon. Minister

for Education? Gandhiji in his last days had emphasized and wanted to do one thing during his life time, namely, all the regional languages should have the Devnagari script. This has been emphasized by Vinobaji also. May I know whether the Government of India has considered this and if so what is their view on this?

PROF. S. NURUL HASAN : We have provided facilities to all those who have tried to write various regional languages through Devnagari script. But we feel this is a matter on which passions may be aroused and it may be considered to be an imposition. We, therefore, want to pursue a policy which will endear Hindi to people who speak their languages rather than create suspicion in their minds that Hindi might ultimately dominate their own languages and may lead to the stultification of their own languages. Therefore, the policy of the Government is that we will provide facilities and encouragement to all other Indian languages. But we have a special duty in so far as Hindi is concerned.

It has been emphasized by several hon. Members that the educational policy deserves to be changed.

I have already stated that we are attempting to bring about a change in the content of education, in the technique of imparting education, in linking up education with the processes of production and the other processes of the community so that it becomes an integral part of the life of the community. But, while we are dealing with this matter, I would submit, Sir, that we feel that equality of educational opportunity is not fully provided by us and it is an admission which I want to make straightaway. If it had been possible for us, not only in terms of money, but also in terms of teachers and other resources, the inputs needed, I would have liked to upgrade all the schools that we have in the country. But, Sir, clearly I feel that this may not be possible within one Plan period. We, are, therefore, proposing—I hope that our proposal finds general acceptance—that we set up in each development block a community primary school which will

have its services of extension available to the entire block and to the other villages there and where 50% of the seats will necessarily be reserved for the weaker sections of the community in that block and where 25% of the total enrolment will be given to the poorer sections of the community which will be given full maintenance allowance so that the parents do not have to buy them other food or clothes or books and they can manage to go through this education in these schools and similarly at the district level we will have a comprehensive school which can again make its services available to all the higher secondary schools in the neighbourhood.

Now, Sir, one school in a district or one school in a block is not adequate to bring about a major change by itself. But we hope that this will be a nucleus so that other schools will start following its example and the new type of curriculum would be made available and the only merit of this curriculum and pattern would be that it would be uniform throughout the country. If we are able to implement this scheme, I hope that some change would be noticeable even at the grass-roots level of the most backward blocks and groups of villages in our country.

Sir, this brings me to a problem which I must place before the honourable House. Every one knows about it though not many friends have made a reference to it in very clear terms and that, Sir, is the question of financial allocations. Most of our plans do require some money. We have done our best to see that the cost is kept down to (the minimum possible so that some impact can be felt all over the country in the countryside, particularly amongst the weaker sections of our society. But, whether in view of the present depressing economic situation we would be able to get adequate allocations, I do not know. I hope we will be able to get it and if we are able to get it, then, Sir, I am personally optimistic that the targets which have been approved by the National Development Council and the strategy which has been followed by the Central Advisory Board of Education can be implemented.

Sir, I very briefly refer to the question of social welfare. I am sorry the hon. lady Member is not present. But I would specifically like to draw the attention of the House to the new programme of integrated child care services, health care and looking after the mothers and providing preschool education to children up to six years of age. We want to link it with the school system so that it will be possible for a child who has already been playing in, so to speak, the compound of the school from the age of 3 and who is being given pre-school training of hand, of mind, of coordination of the senses, whose curiosity has been aroused, to go to the school when he reaches the age of six years when he would be mentally and emotionally prepared to be able to continue that education. This scheme we consider to be extremely important. For this, naturally we will need the help and support of voluntary agencies, and particularly the Central Social Welfare Board and the State Social Welfare Boards. We would like to bring about certain organizational changes in the Social Welfare Boards so that they are able to reach the grass root level, village level. For that, Manila Mandals could be established which would be able to supplement the efforts which would be made at the Government level

AN HON. MEMBER : It will be dominated by upper class women . . .

PROF. S. NURUL HASAN : If it reaches the grass root level, my hon. friend, it will not be dominated by upper class women.

Sir, Shri M. Asad Madani raised the question of recognition of degrees of Deoband. I am quite prepared. Sir, to hold a discussion with him to go into the academic merits if he would be so kind as to discuss this matter with me.

Regarding the monuments, mosques and Madarsa of Bharatpur and Alwar, my officers in the Archaeological Survey of India tell me that no mosque or Madarsa, either in Bhanitpur or in Alwar, is under Central protection and, therefore, I do not think it would be right to blame the Archaeological Department for that.

So far as the mosque in Kudsia Garden 1 is concerned, we broadly accept the prin-

[Prof. S. Nurul Hasan.] ciple, and this is the Government's policy, that at the time of protection if an institution, if a monument, was under worship, then worship shall be permitted in that monument. If at the time of protection, worship was not being carried out in monument, which is protected, then it would not be desirable to permit worship to be started there at any time after the protection has been granted. Now, Sir, according to the information that is given to me, the list of protected monuments which was published in 1928, contains the following description: This mosque shall not be used for religious purposes. But, Sir, if it can be proved that this information is incorrect, that *in fact* worship was going on in that mosque until 1917, Government would be prepared to consider this matter, because the policy is a clear policy that we do not want to stop worship in a monument where it was being carried out at the time of protection. Another point which needs to be explained was raised by my friend, Shri Appan, who is always so kind and generous. He said that merit scholarships are given irrespective of the means of the candidate. Except the National Science Talent Scholarship, there is no other scholarship of the Government of India which is not a merit-cum-means scholarship. The National Science Talent Scholarship has a very specific purpose and the scholarship to Scheduled Tribes is also without any means test. All the other scholarships of the Government of India, like the National Scholarship, National Loan Scholarship, National Scholarship for Study Abroad, etc., have a means test attached to them and the children of the well-to-do people are not eligible to receive these scholarships.

Another point raised by Shri Appan was regarding the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students in various educational institutions. Sir, my Ministry is in entire agreement with the hon. Member that this should be implemented and in the institutions which are under the control of the Ministry, we are taking fairly energetic steps to see that this is being implemented. This year, for example, the Council of Indian Institute of Technology took a decision that if the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates of the requi-

site ability were not available, (then whosoever was available, would be taken and special remedial courses would be provided to them. If the seats were not filled even then, then the seats would be kept vacant rather than satisfying ourselves that we had done our best. I am told that the response has been very good this year. I am going to review the position and if the response is not adequate, then the Institute will go to the potential candidates rather than merely asking the potential candidates to come to the Institute. We sincerely believe that this constitutional obligation has to be implemented by us.

Sir, the point that was raised by Shri Sitaram Singh is again depressing me. I have heard some other complaints also that in many of the village schools, the children and even the teachers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been treated well. I have been working on a proposal that in the code of conduct for teachers we must lay down specific guidelines that if any teacher is found to be guilty of practising untouchability or of ill-treating a Scheduled Castes or Scheduled Tribes student or a fellow teacher, then that would be one of the important grounds for dismissal of the teacher concerned. As several Members have already pointed out, naturally the implementation of this policy will have to be with the State Government. We are already trying to implement it in the Central Schools and in the School\* in the Union Territories. The Delhi School Education Bill has been passed by us and the rules are being drafted. All these points being taken due note of.

The point raised by my hon. friend, Shri Shyamlal Gupta, about the lack of progress insofar as the publication of books in regional languages is concerned, I would like to submit that insofar as I would like concerned, 2,000 titles have already been published or are in the Press. That is to say, the work has been completed. Either the publication has already taken place or it is being published. Many of our South Indian languages have done even better compared to the number of persons involved in producing the books. Therefore, Sir, I am optimistic though naturally I would like the progress to be more.

On a point of personal explanation, I would like to say that I have not suggested to the Executive Council or the Academic Council of Delhi University that they may have a particular pattern of the managing committee of colleges. I will apply my mind only when the amended statutes come to the Visitor for his approval, when I have to give my advice. But till now I have not expressed my own personal opinion in the matter. I think, Sir, you will agree with me that it would be unfair if I were to express my opinion before the University were to formulate its proposals.

Sir, I have also been accused of pampering the teachers. Sir, I plead guilty to it. I pamper the teachers firstly because I myself belong to the same community and I am very proud to be a teacher. It is only incidentally that I have been asked to do this work. I have been a teacher, I hope I will go back to the profession and die as a teacher. I have no intention of giving up teaching. But, Sir, the consideration that is being given to the teachers is not because they create a lot of trouble. The consideration is being given to the teachers because they are the only people who teach. How do you have education without someone teaching and if the teachers do not teach then what are you going to do? How are you going to carry on education? Is it through laws made by this august Parliament or the State Assemblies? Someone has to teach and if the teacher does not teach, who is going to teach? Therefore, Sir, teachers have to be given due consideration, due importance, as has rightly been pointed out in the National Policy Resolution on Education which was approved by this House in 1968 along with the other House.

Sir, I would like finally to again express my gratitude to the hon. Members for the interest they have taken in the work of the Ministry of Education, Social Welfare and Culture and I would beg my hon. friends to forgive me because I have not been able to touch on every point that has been raised in the House, because it is already quarter to seven.

# MESSAGES FROM THE LOK SABHA

**'in ANDHRA PRADESH  
APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1973.**

## **(II) THE DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL, 1972.**

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Andhra Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1973, as passed in Lok Sabha at its sitting held on the 25th July, 1973.

(2) The speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

(")

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on the 25th July, 1973, has adopted the following motion further extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Disturbed Areas (Special Courts) Bill, 1972:—

### MOTION

"That this House do further extend up to the first day of the last week of the next session, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide for the speedy trial of certain offences in certain areas and for matters connected therewith."

Sir, I lay a copy of the Andhra Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1973, on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU):  
The House stands adjourned till 11 o'clock on Thursday, the 26th July, 1973.

The House adjourned at forty-eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 26th July, 1973.